लखनऊ

बुधवार, 1 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 304

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुँचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं- जॉन मैक्सवेल

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi | NIGHT 29° Low

संक्षेप

केतन हत्याकांड में नया मोड़ : सिया के वकील ने भाई साहिल को भेजा 10 करोड़ का नोटिस, आखिर क्या है पूरा विवाद?

पुणे/नई दिल्ली। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को अदालत ने दूसरी बार 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान वडगांव मावल कोर्ट में सिया गोयल के वकील को लेकर नया विवाद सामने आया। अदालत में सिया गोयल ने कहा कि उनके वकील एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव नहीं, बल्कि एडवोकेट विपुल दुशिंग हैं। इससे एक दिन पहले साहिल गोयल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उन्होंने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव को कभी नियुक्त नहीं किया। साहिल के मुताबिक, आशुतोष श्रीवास्तव ने इस मामले में उनसे कभी बातचीत नहीं की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस बारे में आपत्ति जताई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। साहिल ने कहा कि उन्होंने एडवोकेट विपुल दुशिंग को अपना वकील नियुक्त किया है और इस संबंध में अदालत में हलफनामा भी दाखिल किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिया गोयल से लॉकअप में हस्ताक्षर कराए गए। इन आरोपों के बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में आरोप वापस लेने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में ऐसे आरोप दोबारा न लगाने का लिखित आश्वासन देने की मांग की गई है। हालांकि, नोटिस में लगाए गए आरोप एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव के दावे हैं। इस कानूनी नोटिस पर साहिल गोयल की ओर से फिलहाल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पुलिस को बड़ी सफलता, 20 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ अंतर-जिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार

अनंतनाग। जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने एक अंतर-ज़िला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से कुल 2.613 किलोग्राम हेरोइन (ब्राउन शुगर) बरामद की है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई हल्मुल्ला क्षेत्र में नियमित नाका चेकिंग के दौरान की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर जेके 09 बी 2808 नंबर की एक इग्निस कार को रोका। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखे गए हेरोइन (ब्राउन शुगर) के चार पैकेट बरामद हुए। इसके बाद मौके पर ही चालक को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इश्तियाक अहमद मोगल के रूप में हुई है, जो प्राडा, तंगदार का निवासी है। वह अब्दुल रशीद मोगल का पुत्र बताया गया है। प्रारंभिक बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।

योगी ने सपा पर साधा निशाना: 'एक सैफई, दूसरा रामपुर का परिवार ही विकसित हुआ', भर्ती से चाचा-भतीजे करते थे वसूली

आर्यावर्त क्रांति

रामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर जिले में 690 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में विरासत का अपमान होता था, कांवड़ यात्रा तक पर रोक लगाने की बातें होती थीं, सरकारी भर्तियों में वसूली होती थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था, धार्मिक आस्था और विकास तीनों को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगे, फसाद और सांस्कृतिक विरासत के अपमान से जुड़ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में कांवड़ यात्रा, होली, दीपावली, रामनवमी और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजनों में बाधाएं खड़ी की जाती थीं। आज प्रदेश में सभी पर्व बिना किसी रोक-टोक के पूरे उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, प्रयागराज का विकास नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।

'भर्ती निकलते ही चाचा-भतीजे वसूली पर निकल पड़ते थे'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी भर्तियां भ्रष्टाचार और धांधली का माध्यम बन चुकी थीं। भर्ती निकलते ही चाचा-भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे और कई भर्तियों पर अदालत को रोक लगानी पड़ती थी। उन्होंने दावा किया कि अब सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं।

दो परिवारों तक सीमित था विकास

योगी ने आरोप लगाया कि पहले विकास केवल एक सैफई परिवार और दूसरा रामपुर का एक परिवार तक सीमित था, जबकि बाकी प्रदेश विकास से वंचित रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है।

रामपुर के चाकू का सपा ने किया दुरुपयोग

मुख्यमंत्री ने रामपुर के प्रसिद्ध चाकू उद्योग का जिक्र करते हुए कहा कि चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वह डकैती डालने का हथियार बन जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर के चाकू का उपयोग उद्योग और रोजगार बढ़ाने के बजाय जमीनों पर कब्जे करने के लिए किया। योगी ने कहा कि अब वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के जरिए रामपुर के पैचवर्क, जरी-बूटा, वायलिन और चाकू जैसे पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान और बाजार मिल रहा है।

'गरीबों और दलितों की जमीनों पर होते थे कब्जे'

योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में रामपुर में गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जे किए जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोगों को उनकी जमीनों से वंचित किया गया और सत्ता का इस्तेमाल जनता के हितों के बजाय कुछ लोगों के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया और आज रामपुर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

वोल्वो बस ट्रेलर से टकराई, चार की मौत, 25 घायल

दैनिक अमित मेल

मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना राया क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 यात्री घायल हो गए। हादसा माइलस्टोन 112-113 के बीच सुबह करीब 3:35 बजे हुआ, जब गोला बस सर्विस की एक वोल्वो बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। पुलिस के अनुसार हादसे के समय बस में करीब 65 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी महावन और थाना प्रभारी राया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बचाव दल ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल, मथुरा भेजा।

पुलिस ने बताया कि हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 से 25 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जनरल धीरज सेठ बने भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख

नई दिल्ली, एजेंसी। जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वह सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 30 जून, 2026 को सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। उन्होंने सेना में रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।

जनरल धीरज सेठ के सेनाध्यक्ष बनने के साथ ही निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम आज ही सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर मंगलवार को उन्हें नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में सेना द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर

पुष्पांजलि अर्पित की।

जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में उन्होंने भारतीय सेना की बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। अपने चार दशकों के शानदार सैन्य करियर के दौरान, उन्होंने ऑपरेशनल, रणनीतिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उनके इस अनुभव ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा जनरल सेठ कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में विभिन्न स्तर पर कमान संभाल चुके हैं। उनके कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बख्तरबंद रेजिमेंट, पश्चिमी मोर्चे पर एक बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवाद-विरोधी बल शामिल हैं। जनरल धीरज सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल के रहते हुए सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली। गौरतलब है कि सुदर्शन चक्र कोर, भारतीय सेना की एक प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन है। उन्होंने दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया है। यहां तैनाती के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभियानों और औपचारिक जिम्मेदारियों की देखरेख की।

केतन हत्याकांड में नया मोड़ : सिया के वकील ने भाई साहिल को भेजा 10 करोड़ का नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को अदालत ने दूसरी बार 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान वडगांव मावल कोर्ट में सिया गोयल के वकील को लेकर नया विवाद सामने आया। अदालत में सिया गोयल ने कहा कि उनके वकील एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव नहीं, बल्कि एडवोकेट विपुल दुशिंग हैं। इससे एक दिन पहले साहिल गोयल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उन्होंने एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव को कभी नियुक्त नहीं किया। साहिल के मुताबिक, आशुतोष श्रीवास्तव ने इस मामले में उनसे कभी बातचीत नहीं की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस बारे में आपत्ति जताई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। साहिल ने कहा कि उन्होंने एडवोकेट विपुल दुशिंग को अपना वकील नियुक्त किया है और इस संबंध में अदालत में हलफनामा भी दाखिल किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिया गोयल से लॉकअप में हस्ताक्षर कराए गए। इन आरोपों के बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि साहिल गोयल ने उनके खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

राजनाथ सिंह का बड़ा बयान : मजबूत अर्थव्यवस्था, टेक और सिक्योरिटी से बनेगा विकसित भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि 'वाइब्रेंट गुजरात' प्लेटफ़ॉर्म एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है जो विकसित भारत के विज़न में योगदान दे रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मज़बूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा मिलकर एक मज़बूत राष्ट्र की नींव बनाते हैं। वडोदरा में 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यह पहल नए विचारों और अवसरों के ज़रिए गुजरात को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा यह नए विचारों और नई संभावनाओं के ज़रिए गुजरात को आगे ले जाने की कोशिश है। मैंने यहाँ लगी प्रदर्शनी भी देखी। इसमें इंडस्ट्री, MSME, आदिवासी उत्पादों और भारी

उद्योगों सहित कई क्षेत्रों की भागीदारी है। रक्षा उद्योग में हो रहा काम भी तारीफ़ के काबिल है। आप हमें प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। देश के लिए गुजरात के योगदान की तारीफ़ करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कई महान नेता दिए हैं। उन्होंने कहा गुजरात ने देश को महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल दिए, और इसी धरती ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिए। जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, तो दुनिया ध्यान से सुनती है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनका जन्म एक गुजराती माँ की कोख से हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 'वाइब्रेंट गुजरात' पहल शुरू की थी, जो पिछले दो दशकों में एक बड़े आंदोलन में बदल गई है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात मंच गुजरात के लोगों और उद्योगों की जीवंतता को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज यह विकसित भारत के विज़न से जुड़ा एक व्यापक आंदोलन बन गया है। पिछले दो दशकों में इसने गुजरात में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं और आज गुजरात भारत का विकास इंजन बन गया है। सम्मेलन में अपनी भागीदारी के महत्व को समझाते हुए सिंह ने कहा कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ, पुलिस के कई सवालों का नहीं दे पाए जवाब

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। इसी क्रम में पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से करीब तीन घंटे तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पुलिस ने प्रशासनिक फैसलों, चढ़ावे की व्यवस्था, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और शिकायतों के निपटारे से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि कुछ सवालों पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण जरूरत पड़ने पर उनसे दोबारा पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब चंपत राय के बयान का मिलान अन्य गवाहों के बयान, दस्तावेजों और जांच में सामने आए तथ्यों से करेगी। स्ट्रॉन्ज की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया है।

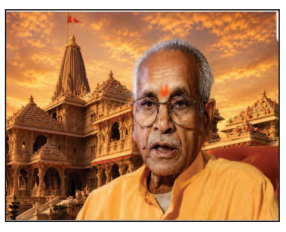

जानकारी के मुताबिक, स्ट्रॉन्ज जुलाई के पहले सप्ताह में अयोध्या पहुंचकर जांच पूरी करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने पुलिस से कहा कि चढ़ावा चोरी मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनका कहना था कि जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल कार्रवाई शुरू कराई, संदिग्धों को पकड़वाया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा, ₹मैंने ही स्ट्रॉन्ज को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ। हालांकि, यह मेरी गलती रही कि शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई और हम पहले आंतरिक जांच करते रहे। चंपत राय ने यह भी स्वीकार किया कि चढ़ावे की व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। टिन्नू यादव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से मंदिर व्यवस्था से जुड़ा था और उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने नियुक्तियों को लेकर भी सवाल किए। रिश्तेदारों या परिचितों को काम दिए जाने के संबंध में चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद और गरीब लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से नियुक्तियां की गई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों का फैसला केवल उनका नहीं, बल्कि ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की सहमति से होता था।

मुझ पर यकीन नहीं तो जयशंकर से पूछिए... यूएस-भारत रिलेशन को लेकर ट्रंप पर भड़के अमेरिकी सांसद

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस सदस्य (सांसद) रो खन्ना ने भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। वॉशिंगटन में आयोजित 'यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट' को संबोधित करते हुए कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद खन्ना ने दावा किया कि पिछले 30 वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। रो खन्ना ने इस कूटनीतिक गिरावट के लिए पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। अपने संबोधन में उन्होंने बेहद बेबाकी से बात रखते हुए कहा कि मैं अपनी बात को घुमा-फिराकर कहने वालों में से नहीं हूँ। जो सच है,

उसे सीधे तौर पर सामने रखना मेरी आदत है। हकीकत यही है कि भारत और अमेरिका के संबंध इस समय पिछले तीन दशकों के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुँच चुके हैं। खन्ना ने विशेष रूप से ईरान के साथ बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना बेहद विनाशकारी साबित हुआ है। इसका सीधा और बुरा असर भारत में ईंधन (गैस और तेल) की कीमतों पर पड़ा है। उन्होंने मंच से कहा कि अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो, तो वे सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में बात कर सकते हैं। अपने दावों को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सांसद ने अपने हालिया चीन दौरे का भी हवाला दिया। उन्होंने समिट में बताया कि चीन यात्रा के दौरान वहाँ तैनात भारतीय राजदूत ने खुद उनसे साझा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और फैसलों के कारण दोनों देशों के बीच सालों से बना 'एक पूरी पीढ़ी का भरोसा' खत्म हो गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पत्नी को मेंटेनेंस देना पति की जिम्मेदारी, मायके की मदद बहाना नहीं

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी परेशान पत्नी को उसके माता-पिता से मदद मिल रही है, तो भी उसका पति गुज़ारा-भत्ता (मेंटेनेंस) देने की अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने पत्नी और उसके दो नाबालिग बच्चों की ओर से बुलंदशहर की फ़ैमिली कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर क्रिमिनल रिविज़न याचिका को मंज़ूरी दे दी। फ़ैमिली कोर्ट ने दिसंबर 2023 में दिए अपने आदेश में पत्नी के गुज़ारा-भत्ते के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, जबकि हर बच्चे के लिए 3,000 रुपये प्रति माह

गुज़ारा-भत्ता तय किया था। पत्नी और उसके दो नाबालिग बच्चों की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को मंज़ूरी देते हुए, जस्टिस गरिमा प्रसाद ने कहा कि पत्नी को CrPC की धारा 125 के तहत पति से गुज़ारा-भत्ता (मेंटेनेंस) देने से सिर्फ़ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मुश्किल समय में उसके माता-पिता उसे आर्थिक मदद देते हैं।

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पत्नी के माता-पिता की आय को उसकी आय नहीं माना जाना चाहिए, और माता-पिता द्वारा दी जाने वाली सहायता पति के पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी दायित्व का विकल्प नहीं हो सकती। पत्नी ने शुरू में अपने पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से वह अपने पति और परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न, ताने और क्रूरता का शिकार रही है। यह आरोप लगाया गया था कि उसका पति, जो याचिका में दूसरा प्रतिवादी है, एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी है, जिसने उससे वैवाहिक संबंध तोड़ लिए और बाद में उसे बताया कि उसने दूसरी महिला से शादी कर ली है।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पीलीभीत कोर्ट में परिवाद दायर, भगवान राम और हनुमान पर टिप्पणी का मामला

आर्यावर्त संवाददाता

पीलीभीत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम व पवनसुत हनुमान के विरुद्ध टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध पीलीभीत के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। इस मामले में 31 जुलाई तिथि नियत की गई।

भगवान श्री राम व हनुमान के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणियां करने पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए परिवाद दर्ज कर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की गई।

अग्रिम तिथि 31 जुलाई नियत की

न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात पीठासीन अधिकारी सतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए परिवाद दर्ज कर सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि 31 जुलाई नियत की।

सार्वजनिक मंच से भगवान पर की थी टिप्पणी

ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नीलेश चतुर्वेदी एडवोकेट ने एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल परिवाद में कहा कि 23 जून को गाजीपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक मंच से भगवान श्री राम व राम मंदिर के साथ हनुमान जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए अमर्यादित व अपमानजनक टिप्पणियां की। उन्होंने सार्वजनिक मंच से हनुमान जी के पौराणिक प्रसंगों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें मामूली सा बंदर कहकर संबोधित किया।

आरोप है कि भगवान राम व उनके मंदिर के लिए भी अशोभनीय टिप्पणी की, जो इंटरनेट मीडिया समेत टीवी चैनलों पर प्रसारित हुई। इससे आहत होकर मां ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नीलेश चतुर्वेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

अयोध्या में अजय राय को नजरबंद करने के बाद धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने लिया हिरासत में

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को हाउस अरेस्ट करने के बाद अयोध्या में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार चौराहे पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उन्हें साथ में पुलिस लाइन ले गई है।

उधर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में अजय राय को रखा गया है। इसकी जानकारी मिलते ही कार्यकर्ता विवि. पहुंच गए। विवि. के मुख्य गेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। बता दें कि अजय राय समेत कई नेताओं को पुलिस ने नजरबंद किया है। आज सभी लोग राम मंदिर में रामलला दर्शन करने वाले थे। दर्शन के बाद ट्रस्ट का घेराव करने का कार्यक्रम था, लेकिन इससे पहले ही कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया।

आजाद वर्मा को नम आंखों से विदाई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में हुई गोलीकांड की घटना के बाद मंगलवार को मृतक आजाद वर्मा का गांव के बाहर बाग में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के दौरान परिजनों और ग्रामीणों में गुस्सा और शोक दोनों दिखाई दिए।

बताया जा रहा है कि रविवार शाम आजाद वर्मा घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के एक निजी स्कूल के पास पहले से मौजूद लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली पीठ में लगने के बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने परिजन की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब तक सूरज, सत्यम और रुपम को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

घटना के बाद परिवार ने प्रशासन के सामने सख्त मांगें रखीं। एएसपी और एडीएम को सौंपे ज्ञापन में परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए परिवार की सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस और कथित रूप से जुड़े ईंट भट्ठे की जांच कर कार्रवाई की भी मांग उठाई। राजनीतिक हलचल के बीच लंभुआ से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा ने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद पीड़ति परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई। वहीं संजय यदुवंशी और आप प्रवक्ता वंशराज दुबे ने भी परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इससे पहले पूर्व विधायक अरुण वर्मा भी पीड़ति परिवार के बीच पहुंचे थे। हालांकि सदर विधायक की गैरमौजूदगी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।

खुद को कुंवारा बताकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया, शादी की बारी आई तो... प्रतापगढ़ में दरोगा पर एफआईआर

आर्यावर्त संवाददाता

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से खाकी वर्दी को दागदार करने वाली एक बेहद गंभीर वारदात सामने आई है। यहां मान्धाता थाने में तैनात एक उप-निरीक्षक (सब-इस्पेंक्टर) पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक शोषण करने और पोल खुलने पर जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले एक मुकदमे के सिलसिले में उसकी मुलाकात मान्धाता थाने में तैनात दरोगा अर्जुन सिंह से हुई थी। आरोप है कि बातचीत के दौरान दरोगा ने खुद को अविवाहित (कुंवारा) बताया और महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद दरोगा ने महिला से शादी करने का पक्का वादा किया।

अलग-अलग होटलों में रखकर एक साल तक किया शोषण

पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर दरोगा अर्जुन सिंह उसे प्रतापगढ़ बुलाता रहा। उसने महिला को शहर के अलग-अलग होटलों में ठहराया और शादी का झांसा देकर लगातार एक साल तक उसका शारीरिक शोषण किया।

शादी का दबाव बनाया तो दी जान से मारने की धमकी

इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब 17 जून 2026 को महिला ने दरोगा पर शादी करने का कानूनी दबाव बनाया। शादी की बात सुनते ही आरोपी दरोगा ने अपना असली रंग दिखा दिया और साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि जब महिला ने विरोध किया तो दरोगा ने उसके साथ अभद्र भाषा में गाली-गलौज की और उसे चुप रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी। बाद में जब पीड़िता ने अपने स्तर पर छानबीन की, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई; उसे पता चला कि दरोगा अर्जुन सिंह पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

धोखाधड़ी और शोषण का अहसास होने पर पीड़िता ने न्याय के लिए उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की तहरीर पर 27 जून 2026 को महिला थाना, प्रतापगढ़ में आरोपी दरोगा अर्जुन सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का भ्रामक वादा करके शारीरिक संबंध बनाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना) और 351(3) (जान से मारने की आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया- मामले की गंभीरता और खाकी की साख को देखते हुए आरोपी दरोगा अर्जुन सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस संवेदनशील मामले की कमान उप-निरीक्षक संगीता को सौंपी गई है। पुलिस पूरी गहराई से साक्ष्य जुटा रही है ताकि पीड़िता को हर हाल में न्याय मिल सके।

बहू से अवैध संबंध के शक में ससुर ने युवक को उतारा मौत के घाट, बिजनौर के इस गांव में तनाव

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मर्यादा और रिश्तों को ताक पर रखकर एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। मंडावर थाना क्षेत्र के कोहरपुर गांव में एक ससुर ने अपने ही बेटे की पत्नी (बहू) और पड़ोसी युवक के बीच कथित प्रेम प्रसंग से नाराज होकर युवक की सरेआम हत्या कर दी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय बिट्टू कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी ससुर सुरेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे की है। बिट्टू कश्यप अपने चचेरे भाई आशु के साथ गांव की ही एक दुकान पर सामान लेने जा रहा था। तभी रास्ते में पड़ोसी सुरेंद्र सिंह चौहान और उसके दो बेटों, अनित और नीटू ने बिट्टू को रोक लिया। बिट्टू और सुरेंद्र के बीच पहले तीखी बहस और गाली-गलौज हुई।

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी सुरेंद्र के दोनों बेटों अनित और नीटू ने बिट्टू को कसकर पकड़ लिया और सुरेंद्र ने अपने पास रखे चाकू से बिट्टू के सीने पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। बिट्टू के भाई आशु ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी हमला करते रहे। हमले के बाद बिट्टू खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा और आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस पूछताछ में ससुर का कबूलनामा

शुरुआती जांच में पुलिस इसे मामूली विवाद या पुरानी रंजिश मान रही थी, लेकिन मुख्य आरोपी सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया। आरोपी सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि बिट्टू उसके खेतों पर मजदूरी करने आता था। इसी दौरान उसकी बहू और बिट्टू के बीच नजदीकियां बढ़ीं।

बार-बार दी थी चेतावनी

सुरेंद्र का दावा है कि उसने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की थी और बिट्टू को अपनी बहू से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन वह नहीं माना। दोबारा साथ देखने पर फूटा गुस्सा फूट गया और रविवार सुबह इसी बात को लेकर फिर से कहासुनी हुई और गुस्से में आकर सुरेंद्र ने अपने बेटों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

घर पर लिखा 'मकान बिकाऊ है'

इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे कोहरपुर गांव में तनाव फैल गया। नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

इतना ही नहीं, सुरक्षा और न्याय न मिलने की आशंका जताते हुए पीड़ित परिवार ने विरोध स्वरूप अपने घर की दीवारों पर 'यह मकान बिकाऊ है' लिख दिया और गांव छोड़ने का एलान कर दिया। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई के आश्वासन और रात में आरोपी सुरेंद्र के मकान की दीवार बुलडोजर से गिराने के बाद परिजन शांत हुए और बिट्टू का अंतिम संस्कार किया जा सका।

पुलिस की कार्रवाई और फरार आरोपियों की तलाश

एसपी सिटी डॉ। कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता चरण सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह चौहान और उसके दो बेटों अनित व नीटू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र को जेल भेज दिया है, जबकि उसके फरार चल रहे दोनों बेटों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

ट्राई सायकिल दिलाकर दिव्यांगो और वरिष्ठजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का सुखद प्रयास

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह लगातार क्षेत्रवासियों की सेवा में तत्पर हैं और उनका प्रयास है कि वे हर किसी की मदद कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं। इसी कड़ी में आज वे धनपतगंज ब्लाक क्षेत्र के कोरों तिराहा बाजार पहुंचे और सतरसुमा कुरुउ विद्यालय में दिव्यांगों और वरिष्ठजनों को ट्राई सायकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दरअसल एलिम्को द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वायोश्री योजना के अंतर्गत इस निःशुल्क ट्राई सायकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता जनार्दन के समक्ष रखा, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ साथ बीजेपी सरकार गरीबों को राशन, आवास, शौचालय के साथ साथ उनकी चिकित्सा, परिवार के वैवाहिक कार्यक्रम सहित तमाम निःशुल्क कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सरकार लोगों की मदद कर रही है। हमारा उद्देश्य भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ लोगों की हर तरीके से मदद करना है, लेकिन ये तब संभव हुआ जब आप सब ने मुझे मौका दिया। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन शत प्रतिशत करने में लगा हुआ हूँ। आप सब साथ दीजिए तो जो अन्य जनसमस्याओं से जुड़े कार्य हैं, उसे भी पूरा करके ही दम लूंगा। संबोधन के बाद उन्होंने वहां मौजूद वरिष्ठ पात्रों और दिव्यांग जनों को ट्राई सायकिल का वितरण किया। वहीं ट्राईसाइकिल पाने के बाद लोगों को चेहरे खिल उठे और उन्होंने बीजेपी सरकार के साथ साथ विधायक विनोद सिंह का भी आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य धर्मेश मिश्रा, कोरो प्रधान शशिबल सिंह, आसरा संचालक सूरज कुमार, आदर्श आसरा टीम के सदस्य कुलदीप पाण्डेय, एलिम्को डॉक्टर की टीम सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

1 जुलाई से स्कूली वाहनों की होगी सघन जांच

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद में 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक मिशन सेफ फ्यूचर के तहत विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट वाले स्कूली वाहनों की सघन जांच की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अलका शुक्ला ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों की फिटनेस अथवा परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है, वे तत्काल उनका नवीनीकरण करा लें। अन्यथा जांच के दौरान उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने जनपद के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों से भी कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केवल वैध फिटनेस और परमिट वाले वाहनों का ही संचालन सुनिश्चित करें। जिन वाहनों के दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें स्कूल परिवहन व्यवस्था में शामिल न किया जाए तथा संबंधित वाहन स्वामियों को शीघ्र नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को केवल ऐसे स्कूली वाहनों से ही विद्यालय भेजें, जिनके सभी आवश्यक दस्तावेज वैध हों। इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सकेगा।

700KM तक... 20 हजार लीटर पानी से नहाते हुए जाएगा हिप्पो सतीश

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर और इंदौर चिड़ियाघर के बीच जल्द ही एक अनूठा एनिमल एक्सचेंज (Animal Exchange) होने जा रहा है। इस अदला-बदली के तहत कानपुर का दरियाई घोड़ा (हिप्पोपोटेमस) सतीश इंदौर का मेहमान बनेगा, जबकि इंदौर से युवा शेरनी 'वीरा' कानपुर चिड़ियाघर के कुनबे को बढ़ाने के लिए यहाँ लाई जाएगी। सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) से इस ट्रांसफर को हरी झंडी मिल चुकी है और तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

इस 700 किलोमीटर लंबे सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए दोनों चिड़ियाघर प्रशासनों ने बेहद अनोखे और पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरियाई घोड़ा एक उभयचर प्राणी है जो अपना 80 प्रतिशत समय पानी में ही बिताता है। उसकी त्वचा को

हमेशा नमी की जरूरत होती है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने इस सफर के लिए बारिश का मौसम चुना है। इसके बावजूद, कानपुर से इंदौर के रास्ते में सतीश के शरीर को नम रखने के लिए ट्रक पर पानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। परिवहन वाले ट्रक में 100-100 लीटर क्षमता के दो पानी के विशेष टैंक रखे होंगे। स्प्रे सिस्टम के जरिए सतीश पर लगातार पानी की बौछार की जाएगी। सफर के दौरान कीपर बीच-बीच में बाल्टी से भी हिप्पो पर पानी डालेंगे। अनुमान है कि पूरे सफर में सतीश करीब 20 हजार लीटर पानी से नहाता हुआ इंदौर पहुंचेगा। इंदौर चिड़ियाघर प्रशासन ने सतीश के लिए 8 बाई 5 बाई 5.15 फीट का विशेष पिंजड़ा तैयार करवाया है, ताकि उसे चोट न लगे और वह आसानी से उठ-बैठ सके।

कानपुर में दहाड़ेगी इंदौर की शेरनी वीरा

कानपुर चिड़ियाघर के शेरों के कुनबे में पिछले 8 वर्षों से किसी नए शावक का जन्म नहीं हुआ है। हाल ही में शेर परिवार के मुखिया बब्बर शेर अजय की मौत के बाद यहां बब्बर शेर शंकर अकेला नर बचा है, जबकि उसकी बहन नंदिनी और मां उमा दो शेरनियां हैं। शंकर को नई जोड़ीदार देने और कुनबा बढ़ाने के लिए इंदौर चिड़ियाघर में जन्मी 3 वर्षीय एशियाई शेरनी वीरा को कानपुर भेजा जा रहा है। वीरा के आने से कानपुर जू में शेरों की दहाड़ फिर तेज होगी।

60 किमी से ज्यादा नहीं होगी ट्रक की स्पीड

सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जानवरों की सुरक्षा के मद्देनजर दोनों तरफ के परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा तय कर दी है। हिप्पो और शेरनी को ले जाने वाले ट्रक 60 किमी प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से नहीं चल सकेंगे।

अधिकारियों का क्या है कहना?

इंदौर चिड़ियाघर के निदेशक उत्तम यादव ने बताया कि वे कानपुर को अपनी युवा शेरनी वीरा गिफ्ट कर रहे हैं और बदले में उन्हें युवा हिप्पो सतीश मिल रहा है, जिसके लिए विशेष पिंजड़ा तैयार है। वहीं, कानपुर जू के निदेशक डॉक्टर कन्हैया पटेल ने पुष्टि की कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही इंदौर की टीम शेरनी को लेकर कानपुर पहुंचेगी, जिसके बाद सतीश को विदा किया जाएगा।

पीएसआई इंडिया देश की 'टॉप 100 मिड-साइज ऑर्गनाइज़ेशन' में शामिल

संस्था ने हासिल की 79वीं शानदार रैंक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर देश के विभिन्न राज्यों में सरकार के साथ मिलकर समुदाय को जनसुविधाओं से जोड़ने का प्रमुखता से कार्य रही संस्था पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पी.एस.आई. इंडिया) को लगातार पांच बार देश के "ग्रेट प्लेसेस टू वर्क" के खिताब से नवाजा गया है। लगातार पांच वर्षों से देश की बेहतरीन कार्यस्थल वाली प्रमाणित स्वयंसेवी संस्था का दर्जा बरक़रार रखे हुए पी.एस.आई. इंडिया को एक और गौरव हासिल हुआ है, मुंबई में आयोजित एक समारोह में ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्था की ओर से पीएसआई इंडिया को देश की 'टॉप 100 मिड-साइज ऑर्गनाइज़ेशन' में शामिल करते हुए सम्मानित किया गया है। ज्ञात हो कि संस्था ने शानदार 79वीं रैंक हासिल की है।

पीएसआई इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने खुशी जताते हुए इसे संस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने लगातार पांच वर्षों से हासिल कर रहे इस प्रतिष्ठित सम्मान को पीएसआई इंडिया बोर्ड के सभी सदस्यों, संस्था के 200 से अधिक सम्मानित कर्मचारियों को समर्पित करते हुए कहा कि पूरी टीम की लगन, कार्यकुशलता और जोश ने ऑर्गनाइज़ेशन को काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाने में योगदान दिया है। पीएसआई इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर समरेंद्र बेहरा, डायरेक्टर एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन संजीव श्रीवास्तव और ऋचा शरद सेल्वी भी सम्मान ग्रहण करने में उनके साथ मौजूद रहे। ज्ञात हो कि देश के 100 से 1000 कर्मचारियों वाली संस्थाओं और कंपनियों के कर्मचारियों के कार्य वातावरण पर फीडबैक और कार्यस्थल के वृहद स्वतंत्र आंकलन के बाद यह सम्मान प्रदान किया जाता है।

मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि पीएसआई-इंडिया को यह सम्मान कार्यस्थल के वृहद स्वतंत्र आंकलन के आधार पर ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्था द्वारा वर्ष 2026 के लिए प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी कर्मचारी कल्याण की प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करेगा। श्री शर्मा ने बताया कि पीएसआई इंडिया को इससे पहले देश की पहली हैपिएस्ट प्लेस टू वर्क (काम करने के लिए सबसे सुखद स्थान) और बेस्ट प्लेस टू वर्क वाली प्रमाणित स्वयंसेवी संस्था बनने का गौरव हासिल हो चुका है। हैपीनेस रिसर्च एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ने संस्था को हैपिएस्ट प्लेस टू वर्क का प्रमाणपत्र प्रदान किया था। यह सभी प्रमाणपत्र कर्मचारी कल्याण और सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुकेश कुमार शर्मा ने इस उपलब्धि पर ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि एक खुशहाल दुनिया बनाने की हमारी यात्रा का एक अहम हिस्सा है। हम भरोसा दिलाते हैं कि संस्था इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का कार्य करती रहेगी। उन्होंने बताया कि संस्था कर्मचारियों को एक पारिवारिक माहौल प्रदान करने के साथ ही उनकी सुख-सुविधाओं और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखती है।

संक्षेप

निजी अनुरोध पर 13 वरिष्ठ सहायकों के तबादले, राजस्व परिषद ने जारी किया आदेश

लखनऊ। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने जनपद कार्यालयों में कार्यरत 13 वरिष्ठ सहायकों का उनके निजी अनुरोध पर स्थानांतरण कर दिया है। इस संबंध में परिषद की ओर से 29 जून 2026 को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया ।जारी आदेश के अनुसार शायना परवीन का अलीगढ़ से हरदोई, दीपक कुमार शर्मा का हरदोई से अलीगढ़, आशीष भारद्वाज का बुलंदशहर में ही समायोजन, रामगोपाल उपाध्याय का अलीगढ़ से लखनऊ, स्नेहा देवी का कानपुर नगर से अलीगढ़ तथा सोनम दुबे का कानपुर नगर से लखनऊ स्थानांतरण किया गया हैइसी प्रकार राजेश कुमार मौर्य का प्रयागराज में ही समायोजन, राधा रमण चौधरी का बस्ती से बलिया, अमजद अली का खीरी से बलिया, संजीव कुमार यादव का प्रयागराज से खीरी, पवन कुमार वर्मा का शाहजहांपुर से हरदोई, मनोज कुमार सिंह का हरदोई से शाहजहांपुर तथा संजय कुमार गौतम का शाहजहांपुर से हरदोई स्थानांतरण किया गया है ।राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरण आदेश में उल्लिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन प्रभावी होंगे तथा संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएसओ चौराहे पर महिला से मारपीट व अभद्रता, दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। हजरतगंज थाना क्षेत्र के डीएसओ चौराहे के पास वाहन आगे-पीछे करने को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है ।पुलिस के अनुसार 28/29 जून 2026 की रात डीएसओ चौराहे के पास वाहन हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर हजरतगंज थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया ।घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आवश्यक विवेचनात्मक एवं विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

सरोजनीनगर में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

लखनऊ। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के अनौरा गांव में 21 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उपचार के लिए लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया ।पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान श्रद्धा सोनकर (21) पुत्री ओमप्रकाश सोनकर, निवासी अनौरा, थाना सरोजनीनगर के रूप में हुई है। मंगलवार को सूचना मिली कि युवती ने अपने आवास पर पंखे से फांसी लगा ली है ।घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया ।पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की मर्चरी भेज दिया है ।पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य है।

महिगवां में किराये के कमरे में युवक ने लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ। महिगवां थाना क्षेत्र में किराये के कमरे में रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट की सहायता से घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान बब्लू रावत (30) पुत्र मथुरा रावत, मूल निवासी ग्राम लम्बापुरवा (मजरा सरौरा), थाना अटरिया, जनपद सीतापुर के रूप में हुई है। वह महिगवां थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में अमर सिंह यादव के मकान में किराये पर रहकर काम करता था ।मंगलवार को मृतक के पिता मथुरा रावत ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पुत्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। इसके बाद फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट और परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा खोलकर शव को नीचे उतारा गया तथा घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए ।पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की मर्चरी भेज दिया है ।पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लगाया जाएगा। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य है।

मोहनलालगंज में डंपर से टकराई पिकअप, चालक की मौत; आरोपी चालक गिरफ्तार

लखनऊ। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के भवनखेड़ा के पास हुए सड़क हादसे में एक पिकअप चालक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है ।पुलिस के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे भवनखेड़ा के पास सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि टाटा पिकअप वाहन संख्या UP33DT7717, जिसे विकास सिंह (30) निवासी ग्राम धावापुर, थाना बंथरा चला रहे थे, की डंपर संख्या UP78HN0552 से टक्कर हो गई ।हादसे में विकास सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मोहनलालगंज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया ।पुलिस ने घटना के बाद डंपर चालक को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके भाई को सौंप दिया गया ।पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर स्थिति सामान्य रही और कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई।

यूपीटीईटी-2026 परीक्षा में शामिल शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश, शासन ने जारी किया आदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देने वाले कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक टीईटी में शामिल हो रहे हैं। शासन के इस निर्णय से लंबे समय से छुट्टी की मांग कर रहे शिक्षकों को बिना प्रशासनिक बाधा परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 2, 3 और 4 जुलाई को यूपीटीईटी-2026 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक शामिल होंगे। इसे देखते हुए शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को परीक्षा तिथियों के लिए विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्य किए जाने के निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.80 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इसमें से काफी शिक्षक यूपीटीईटी में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए विभिन्न शिक्षक संगठन परीक्षा तिथि के लिए छुट्टी देने की मांग कर रहे थे। शासन की ओर से आदेश जारी करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है।

भाजपा सरकार की नीतियों से किसान संकट में, 2027 में किसान बदलाव लाएगा : अखिलेश यादव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का किसान गंभीर संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।अखिलेश यादव ने कहा कि खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल की बढ़ती कीमतों ने खेती को महंगा बना दिया है। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन बढ़ती लागत के कारण किसानों की आमदनी पहले से भी कम हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने में विफल रही है, जिससे किसान परेशान हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम वर्षा की आशंका के बीच धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। किसानों को पर्याप्त बिजली और सिंचाई की सुविधा भी नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में नकली बीज और दवाइयां बिक रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और बिचौलिये इसका लाभ उठा रहे हैं।सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका सबसे अधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।अखिलेश यादव ने दावा किया कि किसानों में भाजपा के प्रति आक्रोश है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा को सत्ता से हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा।

अस्थि-कलश के संभावित स्थानांतरण के विरोध में आरपीआई का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ने 10, विधानसभा मार्ग स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा परिसर में स्थापित पावन अस्थि-कलश और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के संभावित स्थानांतरण के विरोध में मंगलवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अटल चौक से विधानसभा मार्ग तक पैदल मार्च निकालने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 10, विधानसभा मार्ग स्थित परिसर बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए आस्था और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है तथा यहां स्थापित पावन अस्थि-कलश, बौद्ध विहार, आनंद बोधिवृक्ष और बाबा साहेब की कांस्य प्रतिमा को किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जाना चाहिए।प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मार्च रोके जाने पर कुछ समय के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। बाद में कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा।इस अवसर पर पवन भाई गुप्ता ने कहा कि 10, विधानसभा मार्ग स्थित परिसर केवल एक भवन नहीं, बल्कि बाबा साहेब के अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।

उत्तर प्रदेश टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेज सर्वे-2025 रिपोर्ट जारी, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए 10 प्रमुख सिफारिशें

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन (एलएलएफ) ने टाटा ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेज सर्वे (टीएलपीएस)-2025 रिपोर्ट का विमोचन किया। रिपोर्ट में कक्षा 1 और 2 के शिक्षण-अधिगम व्यवहारों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कक्षा-कक्ष की गुणवत्ता सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित सुझाव दिए गए हैं।रिपोर्ट का विमोचन अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थसारथी सेन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, एससीईआरटी निदेशक गणेश कुमार, समग्र शिक्षा के अधिकारियों, टाटा ट्रस्ट, एलएलएफ, डायट, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति में किया गया। यह कार्यक्रम ₹पॉलिसी टू प्रैक्टिस डायलॉग: ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम प्रैक्टिसेज₹ विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा नीति और विद्यालयी शिक्षण के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई।रिपोर्ट के लिए नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच बहराइच, बरेली, मिर्जापुर और रायबरेली के 200 विद्यालयों तथा 200 कक्षाओं का अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण के दौरान कक्षा-कक्ष के वातावरण, पाठ संचालन, समय के उपयोग और शिक्षकों के साक्षात्कार के माध्यम से छह प्रमुख आयामों—कक्षा वातावरण, पाठ योजना एवं संचालन, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, समय प्रबंधन और शिक्षक दृष्टिकोण—का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के कई सकारात्मक पक्ष सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार 97 प्रतिशत कक्षाओं में कार्यशील श्यामपट्ट उपलब्ध मिले, 97 प्रतिशत शिक्षक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) के अधिगम लक्ष्यों से परिचित पाए गए, 94 प्रतिशत शिक्षकों को क्लस्टर और ब्लॉक संसाधन समन्वयकों से शैक्षणिक सहयोग प्राप्त हुआ तथा 78 प्रतिशत शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम मूल्यांकन का लिखित अभिलेख रखते मिले।हालांकि रिपोर्ट में समावेशी शिक्षण को और मजबूत बनाने, बेहतर पाठ योजना तैयार करने, विद्यार्थियों को प्रभावी प्रतिपुष्टि देने, कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने, भाषा और गणित शिक्षण को अधिक संवादात्मक बनाने तथा शिक्षकों के सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण और सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन ने निर्देश दिए कि रिपोर्ट में शामिल 10 प्रमुख सिफारिशों पर आगामी शिक्षक क्लस्टर बैठकों में अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए।

बंद मकान पर थी चोरों की नजर, गुडम्बा पुलिस ने 48 घंटे में किया चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के गुडम्बा थाना क्षेत्र में बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले दो शातिर युवकों को पुलिस ने घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के बड़ी मात्रा में आभूषण, एक कलाई घड़ी तथा नकद सिक्के बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई दिनों से बंद पड़े मकान की रेकी की थी और मौका मिलते ही ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था ।पुलिस के अनुसार 28 जून 2026 को मोहम्मदपुर खत्री, कल्याणपुर निवासी प्रशांत मणि त्रिपाठी ने गुडम्बा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए हैं। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई ।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से साक्ष्य जुटाए और मुखबिरों को सक्रिय किया। सुरागरसी के दौरान मंगलवार को उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सौरव नेहवाल तथा पुलिस टीम ने कुकरैल जंगल क्षेत्र से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उनकी पहचान मयंक वर्मा (19) निवासी ग्राम भंडार, बड़ुपुर थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी, हाल निवासी मैकाले तिराहा, गुडम्बा तथा अभिषेक यादव (20) निवासी कंचना विहारी मार्ग, कल्याणपुर, गुडम्बा के रूप में हुई ।तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के चार सोने की अंगूठियां, एक मंगलसूत्र, दो सोने की चेन, एक हार, दो जोड़ी बालियां, नथ की लड़, दो सुई-धागा, एक लॉकेट, तीन जोड़ी टॉप्स, नाक की कील, नथुनी, नग सहित दो नाक की कील, चांदी की करधनी, हाफ पेटी, आठ पायल, कमर की चेन, बच्चों के दो कड़े, चार बिछिया, एक कलाई घड़ी तथा एक और दो रुपये के कुल 138 रुपये के सिक्के बरामद किए ।पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने देखा था कि संबंधित मकान कई दिनों से बंद पड़ा है। इसके बाद दोनों ने मकान की रेकी की और रात के समय ताला तोड़कर घर में रखे जेवर और नकदी चोरी कर ली। आरोपियों ने बताया कि चोरी की नकदी वे खर्च कर चुके थे, जबकि आभूषण बेचने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ।गुडम्बा पुलिस ने चोरी का अधिकांश सामान बरामद कर मामले का सफल अनावरण कर दिया है।

बैग में तमंचा लेकर राजधानी के हाईकोर्ट पहुंच गए बाबा, स्कैनिंग के दौरान शक हुआ; थैला देख चौंके पुलिसकर्मी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। हाईकोर्ट के गेट नंबर छह पर चेकिंग के दौरान एक बाबा के बैग से तमंचा और चार करतूस बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने विभूतिखंड थाने में केस दर्ज कराया। इसके बाद बाबा और उनके साथ मौजूद युवक को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

इंस्पेक्टर दीपक कुमार के मुताबिक 25 जून को दरोगा अखिलेश पांडेय को ड्यूटी चेकिंग अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। गेट पर संदिग्ध लोगों और वस्तुओं कह चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच अमेठी के बाजार शुक्ल स्थित मकदूम कला निवासी बाबा अमरदास उर्फ बाल भगवान दास प्रवेश के निर्धारित हरी पर्ची के साथ पहुंचे। बाबा अमरदास के पास एक थैला भी था। बाबा के साथ उनके सहयोगी ओमश्री पांडेय भी मौजूद थे। थैले की स्कैनिंग के दौरान उसमें संदिग्ध वस्तु नजर आई। इसके बाद थैले को पुलिस ने बाबा के सामने खोलकर चेक किया तो भीतर तमंचा और कारतूस मिले। पूछताछ करने पर अमरदास कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

इसके बाद विभूतिखंड पुलिस को घटना के बारे में बताया गया। अमरदास की उम्र 30 वर्ष है। वह एक मामले की पैरवी में अधिवक्ता अमिताभ शुक्ला से मिलने आए थे। पुलिस ने अधिवक्ता को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि अवैध असलहा रखने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। असलहा कहां से आया, इसके बारे में अमरदास ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है।

नागरिकता के दस्तावेजों पर इतना भ्रम ठीक नहीं..

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गया है। इसकी वजह तकनीकी क्रांति तो है ही, लेकिन सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया है। पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी दस्तावेज माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद होगा ही। तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नही है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के शब्दों से गुजरें तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना गलत भी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के विशेष और गहन परीक्षण के दौरान जब घोषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना उसकी नागरिकता के सबूत नहीं है और अब पासपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर भारतीय नागरिक क्या करे। जरूरत पड़ने पर वह कैसे साबित करे कि वह भारतीय नागरिक है। इस आधार पर तो देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता को तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज के दौर की तमाम लड़ाइयों का बुनियादी और मजबूत आधार चूंकि नैरेटिव बन गया है तो यह भी साबित करने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसके लपेटे में मोदी समर्थक ताकतें भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी पर तो खैर सवाल उठेगा ही। इस नैरेटिव को खड़ा होने से पहले ही जरूरी है कि नागरिकता के वैध दस्तावेज को लेकर जारी भ्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अन्यथा भ्रम का यह कुहासा जितना फैलेगा, वह आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और क्षोभ भरेगा। इससे तनाव बढ़ाने वाली ताकतों को भी मौका मिलेगा। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जो कहा है, वह गलत भी नहीं है। अपने देश में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। जबकि भारत में नागरिकता की व्याख्या और प्रमाणिकता के लिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। बस शर्त यह होगी कि सरकार को ऐसा लगे कि उसके लिए पासपोर्ट जारी करना व्यापक जनहित में जरूरी है। इस कानून से साफ है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। बेशक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 भारत सरकार को छूट देती है कि व्यापक जनहित में वह भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता प्रमाणित करने के तीन अभियुक्तों समेत चार लोगों के दावे को बांबे हाईकोर्ट 2013 में ही खारिज कर चुका है। उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए पासपोर्ट पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने दो सितंबर 2013 के अपने फैसले में साफ कर दिया था कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पेश कर सकते। वैसे आधार कार्ड का कानून भी मानता है कि आधार कार्ड सिर्फ निवास और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कानून 2016 की धारा में साफ लिखा है कि आधार कार्ड से नागरिकता की बजाय सिर्फ निवास स्थान और पहचान प्रमाणित होता है। इसकी वजह यह है कि आधार कानून के तहत 182 दिनों तक भारत में लगातार रहने वाले व्यक्ति को सरकार चाहे तो आधार कार्ड जारी कर सकती है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है। इसी तरह पैन कार्ड के लिए भी व्यवस्था दी गई है। पैन कार्ड का कानूनी आधार है कि व्यक्ति अर्जन कर रहा है और टैक्स दे रहा है। आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इन जटिलताओं की समझ है, शायद यही वजह है कि उनके कार्यकाल में देश के सैकड़ों गैरजरूरी कानूनों को या तो रद्द किया गया है या फिर कुछ नए संदर्भों वाले कानूनों में समाहित कर दिया गया है। आज के दौर में नागरिकता के दस्तावेज के रूप जब पासपोर्ट, आधार कार्ड , पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को आखिरी और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार किया जाता है तो अपनी लोक और आम धारणा के चलते आम आदमी इसके विरोध में उतर आता है।

नीली क्रांति से समृद्धि की ओर

मछली पालन बना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आधार

धनंजय राठौर

ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन सीमित भूमि और कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तालाब, जलाशय, नहर और अन्य जल स्रेतों का उपयोग कर किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं में मछली पालन आज केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन गया है। कम लागत, कम समय में बेहतर उत्पादन और बाजार में बढ़ती मांग के कारण यह व्यवसाय गांवों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी किसानों से आह्वान किया है कि वे खेती को केवल धान तक सीमित न रखें। दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक व्यवसायों को अपनाएं। इसी सोच के अनुरूप भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन सीमित भूमि और कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तालाब, जलाशय, नहर और अन्य जल स्रोतों का उपयोग कर किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। बढ़ती आबादी और पौष्टिक भोजन की मांग से मछली की खपत लगातार बढ़ रही है। प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर मछली स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

मत्स्य पालन न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि मत्स्य बीज उत्पादन, आहार निर्माण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के बड़े अवसर देता है।

छत्तीसगढ़ सरकार मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता दे रही है। आधुनिक तकनीकों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण में तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, रोग नियंत्रण और विपणन की जानकारी दी जाती है। तकनीकी उन्नयन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी होते हैं। प्रगतिशील मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर सफल मॉडल देखने भेजा जाता है, ताकि वे नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हों।

उत्पादन और विपणन व्यवस्था मजबूत करने के लिए मत्स्य सहकारी समितियों को आर्थिक मदद दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नाव-जाल देकर पारंपरिक मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आइस बॉक्स, तराजू जैसे उपकरण देकर छोटे मछुआरों को बेहतर बाजार और लाभ दिलाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग को स्पॉन संवर्धन और झींगा सह मछली पालन के लिए विशेष सहायता मिल रही है।

केंद्र-राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से चल रही इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन और मछुआरों की आय बढ़ाना है।

मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने और नए तालाब निर्माण के लिए आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। बेहतर वृद्धि के लिए संतुलित आहार, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (क्ररस) जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मत्स्य पालन के क्षेत्र में सजावटी मछली पालन इकाइयों और जलाशयों में केज कल्चर से स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

मत्स्य पालकों को शीत संयंत्र, प्रशीतित वाहन, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, ई-रिक्शा और लाइव फिश सेंटर से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखकर बेहतर विपणन सुनिश्चित हो रहा है।

मछली पकड़ने की बंद (15 जून से 15 अगस्त तक) अवधि में आर्थिक मदद के लिए केंद्र-राज्य के सहयोग से यह योजना चल रही है।

मत्स्य पालकों के दुर्घटना, मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मछुआरों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

मछली पालन आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का अहम माध्यम बन गया है। सरकार की योजनाएं किसानों, युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को स्वरोजगार के नए अवसर दे रही हैं। आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं।

मत्स्य पालन आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम

इच्छुक हितग्राही अपने नजदीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मछली पालन न सिर्फ आय बढ़ाने का जरिया है, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।

लेखक संयुक्त संचालक जनसंपर्क, रायपुर हैं

टिप्पणी

अब कीमत चुकाने का वक्त

अमेरिका का मकसद एआई तकनीक में अपने करीब किसी को ना पहुंचने देना है। इस तरह वह फ्रंटियर एआई मॉडलों को राष्ट्रीय-सुरक्षा संपत्ति में बदल रहा है, जिन्हें अब तक वाणिज्यिक उत्पाद समझा जाता था।

अमेरिका ने एंथ्रोपिक कंपनी के दो सबसे उन्नत एआई मॉडलों फेबल-5 और माइथोस-5 तक विदेशी नागरिकों की पहुंच रोक दी है। यह प्रतिबंध न केवल अमेरिका से बाहर मौजूद यूजर्स पर लागू हुआ है, बल्कि अमेरिका-वासी विदेशी नागरिक भी इन मॉडलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिनमें खुद एंथ्रोपिक कंपनी के विदेशी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसे अमेरिका सरकार की प्रतिमान बदल देने वाली कार्रवाई समझा गया है। स्पष्टतः इसे सिर्फ सेंसरशिप या साइबर सुरक्षा के जाने-पहचाने नजरिए से देखना उचित नहीं होगा।

यहां अमेरिका ने प्रतिबंध सिर्फ अपने शत्रु या प्रतिद्वंद्वी देशों पर नहीं, बल्कि तमाम देशों के नागरिकों पर लगाई है, जिसमें उसके सहयोगी और दोस्त देश भी शामिल हैं। इसे रेखांकित किया जाना चाहिए कि एंथ्रोपिक कंपनी को आदेश देते वक्त डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने कारण वैश्विक एआई सुरक्षा को बढ़ावा देना, जिम्मेदार आविष्कार का समर्थन, या खुलापन वाले तकनीकी माहौल का निर्माण- नहीं बताया। बल्कि दो टूक कहा कि मकसद एआई के क्षेत्र में अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखना है। कहा कि ये कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका एआई आविष्कार में सबसे आगे बना रहे। कहा जा सकता है कि अमेरिकी सरकार की यह असामान्य रूप से ईमानदार भाषा है।

यह बताती है कि उसके लिए मुद्दा सबसे नई तकनीक में अमेरिकी ताकत के करीब किसी को ना पहुंचने देना है। इस तरह अमेरिका सरकार ने अग्रणी (फ्रंटियर) एआई मॉडलों को राष्ट्रीय-सुरक्षा संपत्ति में बदलने की शुरुआत कर दी है, जिन्हें अब तक वाणिज्यिक उत्पाद समझा जाता था। भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों की कंपनियों और संस्थाओं की समझ थी कि वे फीस चुका कर अमेरिका में विकसित हो रही नई तकनीक का फायदा उठाते रह सकेंगे। मगर अब साफ कर दिया गया है कि किस तकनीक की किस हद तक सेवा वे खरीद सकेंगे, यह अमेरिका सरकार तय करेगी। अब यह भारत जैसे देशों को सोचना है कि उनके सामने क्या विकल्प है और अमेरिकी तकनीक के भरोसे चलना कितना मुफीद है? सच यह है कि तकनीक संप्रभुता पर ध्यान देकर भारत ने अपने हितों से समझौता किया है। अब कीमत चुकाने का वक्त है।

ब्लॉग

रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत बढ़ रही न्यायिक सुगमता

अर्जुन राम मेघवाल

न्याय सदा से ही मानव सभ्यता का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न स्तंभ रहा है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा तथा उसके स्थायी प्रतीक सामूहिक रूप से उन संस्थागत व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता की विकास यात्रा को सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया और निरंतर आगे बढ़ने में सहायता की। मानव सभ्यता के अनवरत विकास के फलस्वरूप ज्ञान-विज्ञान और तकनीक से समृद्ध आधुनिक समाज में एक-दूसरे से जुड़े व्यक्तियों और समुदायों के आपसी संबंधों में भी विभिन्न विचारों और मतों के कारण परिवर्तन आया है, तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी उन्नति ने देश की सीमाओं से आगे जाकर विचारों के निर्बाध आदान-प्रदान को और अधिक सुगम बनाया है। अनादि काल से, एक विचार की दूसरे विचार पर श्रेष्ठता स्थापित करने की होड़ न्यायशास्त्र के विकास की एक मजबूत नींव रही है। युगों से विचारों और मूल्यों के इस अंतर्संघर्ष के बीच न्यायिक संस्थानों ने सत्य, निष्पक्षता और विधि के शासन में लोगों के विश्वास को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी निभाई है। इन्होंने एक सेतु का काम किया है जो प्रत्येक संबंधित पक्ष को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो स्वयं को अलग-थलग महसूस करते हैं, न्याय और सामूहिक कल्याण की एक व्यापक प्रक्रिया से जुड़ाव, विश्वास और सहभागिता का अनुभव कराता है।

इसी स्थायी संस्थागत प्रतिबद्धता के कारण एक ऐसी सशक्त व्यवस्था निर्मित होती है जो न केवल न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए अनिवार्य है। वर्तमान संदर्भ में विकसित भारतीय न्यायशास्त्र ने स्वयं को आधुनिक चुनौतियों और उपलब्ध अवसरों के अनुरूप ढाल लिया है। हमारी संवैधानिक विरासत हमें स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं का स्वप्न साकार करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में सतत मार्गदर्शन प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय की त्रिवेणी अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श संस्थाओं और व्यक्तियों दोनों के लिए एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करते हैं।

स्वतंत्र भारत को संविधान के रूप में एक आदर्श मार्गदर्शक प्राप्त हुआ जिसने हमारे राष्ट्र की प्रगति की दिशा निर्धारित की। देश की आजादी के बाद यद्यपि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, फिर भी गहरी जड़ें जमा चुकी औपनिवेशिक मानसिकता भारतीय चिंतन और मूल्यों के लिए एक बौद्धिक अवरोध बनी रही। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, उसके बाद भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए दंडात्मक कानून तथा विभिन्न नीतियों ने नियमों का एक जटिल जाल बुन दिया, जिसने देश की जनता की स्वतंत्रता को सीमित किया। 19वीं सदी की मानसिकता और 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते।

हमें अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों पर अपार गर्व है। फिर भी, जब हम मोदी सरकार की बारह वर्षों की विकास यात्रा पर नजर डालते हैं तो शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट और सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है जिसने नागरिकों के जीवन को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है। वर्ष 2014 को हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। यह वह वर्ष था जबकि देश में युवाओं की विशाल आबादी को देश के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाले तीव्र गति से विकसित हो रहे भारत की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया गया।

देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में संपूर्ण शासन व्यवस्था ने रिफॉर्म एक्सप्रेस से प्रेरित विकास की प्रक्रिया को तेजी से अपनाते हुए सशक्तिकरण की शक्ति का परिचय दिया है। इसकी यात्रा को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि यह जमीनी स्तर से 'ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने का प्रयास है। साथ ही, राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण को शीर्ष स्तर से लागू करना भी इसका उद्देश्य है।

इसी प्रकार, भारत की न्यायिक सुधारों की यात्रा भी व्यापकता, नवाचार और गहन सामाजिक एवं सभ्यतागत प्रतिबद्धता की एक प्रेरक गाथा रही है। यह एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें विधायी आधुनिकीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और डिजिटल नवाचार शामिल हैं।

'ईज ऑफ जस्टिस हमारे लिए मात्र एक कथन नहीं है बल्कि यह एक सुधार का मंत्र है जिसमें न्याय के लिए अदालत की शरण में जाने वालों के लिए 'ईज ऑफ इंगेजमेंट, अधिवक्ताओं और न्यायाधिशों के लिए 'ईज ऑफ वर्किंग तथा नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल है।

न्याय हेतु अदालतों की शरण में जाने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए दिशा योजना के तहत टेली-लॉ, न्याय बंधु और प्रो बोनो सेवाओं के विस्तार ने न्याय प्राप्ति को अत्यंत सुलभ और किफायती बना दिया है। कॉमन सर्विस सेंटर के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संचालित टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के 112 लाख से अधिक लाभार्थियों को अदालतों में मुकदमे दायर करने से पहले मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करने का लाभ मिला है। ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्र की सेवाओं ने अदालत में मुकदमा दायर करने वाले व्यक्तियों और न्यायिक व्यवस्था के बीच नियमित संवाद एवं संपर्क को और अधिक सरल बनाया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता के समन्वय का भारत का यह अनूठा मॉडल वैश्विक स्तर पर एक मानक के रूप में उभरा है।

अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए 'ईज ऑफ वर्किंग को डिजिटल और भौतिक अवसंरचना दोनों में व्यापक विस्तार द्वारा उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है। चूंकि जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका देश के अधिकांश नागरिकों के लिए न्यायिक व्यवस्था का पहला संपर्क बिंदु है, अतः इसे सुदृढ़ करना एक अनिवार्य और व्यावहारिक प्राथमिकता बनी हुई है। इसी दृष्टि से, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत न्यायालय भवन, अधिवक्ता कक्षों, आवासीय इकाइयों तथा डिजिटल अवसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, देश में न्यायालय भवनों की संख्या वर्ष 2014 के 15,818 से बढ़कर 22,712 हो गई है तथा अत्याधुनिक एकीकृत न्यायालय परिसरों के विकास हेतु वर्ष 2014 के बाद से अब तक 9,400.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 7200 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से शुरू की गई ई-कोर्ट चरण-ढ्ढढ्ढ परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों को पूर्णतः डिजिटल, पेपरलेस और एआई-सक्षम न्याय वितरण संस्थानों में परिवर्तित करना है। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, वर्चुअल कोर्ट और अदालती कार्यवाही की लाईव स्ट्रीमिंग जैसी पहलों ने न्यायपालिका को लोगों के और करीब ला दिया है तथा न्याय वितरण को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाया है।

भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग का होना 'ईज ऑफ जस्टिस के व्यापक ढांचे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर और भाषिणी जैसे एआई- संचालित नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उपकरण उच्चतम न्यायालय के निर्णयों एवं आदेशों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, जिससे आम जनता के लिए कानूनी जानकारी अधिक सुलभ हो रही है। इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो एक सांख्यिकीय एवं विश्लेषणात्मक मंच है, 340 मिलियन से अधिक अदालती आदेशों एवं उनसे संबंधित जानकारियों के विशलेषण तक एक क्लिक में पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, सरकार शिक्षाविदों के सहयोग से सरल और सहज विधायी प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) को बढ़ावा दे रही है ताकि कानूनों को अधिक सरल और आम नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सके।

भारत में औपनिवेशिक दंड संहिता के स्थान पर नई आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने से दाण्डिक व्यवस्था के स्थान पर न्यायिक व्यवस्था स्थापित हुई है। ई-कोर्ट, ई-प्रोसीक्यूशन, ई-प्रिजन और ई-फोरेंसिक को अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के साथ जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम है। न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म ने वर्चुअल उपस्थिति और गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को इतनी कुशलता से सुगम बनाया है कि जब कोई अदालत किसी नागरिक को जमानत देती है, तो डिजिटल जमानत आदेश तुरंत जेल पोर्टल पर पहुंच जाता है जिससे कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक देरी समाप्त हो जाती है, जो पारंपरिक रूप से समय पर रिहाई में बाधा डालती थी। यह वास्तविक समय में केस डेटा के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है और एक अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करता है।

उच्च न्यायपालिका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी सार्थक उपाय किए गए हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 के 906 से बढ़कर 1122 हो गई है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी 31 थी जिसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 34 कर दिया गया है तथा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से इसे बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में देश के उच्च न्यायालयों में सामाजिक रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले 1175 न्यायाधीशों की तथा उच्चतम न्यायालय में 77 न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के समन्वित प्रयासों को दर्शाती है।

यह स्पष्ट है कि अनावश्यक कानूनों की जटिलता संबंधित पक्षों पर अनावश्यक बोझ डालती है। 40,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करने तथा औपनिवेशिक युग के 1725 निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने से विभिन्न क्षेत्रों में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही, आर्बिट्रेशन संबंधी कानूनों को सुदृढ़ करना, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा मेडिएशन एक्ट 2023 के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।

वर्तमान में जबकि विश्व जटिल भू-राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, भारत के विधिक और राजनयिक नेतृत्व ने ब्रिक्स देशों के न्यायमंत्रियों की बैठक, 2026 के दौरान मेडिएशन और आर्बिट्रेशन को विवाद समाधान के लिए अधिक प्रभावी और सुलभ माध्यम के रूप में स्थापित करने हेतु एक सामूहिक प्रतिबद्धता के रूप में गांधीनगर घोषणा पत्र को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे वैश्विक सहयोगों का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना, व्यापार और निवेश के लिए स्थिर एवं सुविचारित परिवेश को सृजित करने पर अत्यधिक बल देना तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना है।

राम मंदिर चंदा चोरी: 'ट्रस्ट में मुसलमान होता तो, एनकाउंटर होता, फिर केस क्लोज', चढ़ावा घपले पर ओवैसी का हमला

'सपा हमेशा मुसलमानों के वोट की राजनीति करती रही है'

जनसभा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. मेहताब चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा हमेशा मुसलमानों के वोट की राजनीति करती रही है और अब उसे छोड़ने का समय आ गया है।

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 70 साल से राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने मुसलमानों से जागरूक होने का आह्वान किया।

सोमवार रात आजाद चौक के निकट जनसभा में ओवैसी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को केवल वोट की राजनीति और दरी बिछाने तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती, जबकि सपा ने उन्हें गुलाम बनाकर रखा है।

उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यदि वे केवल वोटर बनकर रहेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा और बुजुर्गों के लिए अस्पताल भी नहीं बनेंगे। भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि 200 साल पहले मस्जिदें थीं, थाने नहीं थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि संभल की मस्जिद को शहीद कर दिया गया है और अब अन्य मस्जिदों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वह बिजनौर और नजीबाबाद में लोगों को नेता बनाने आए हैं। इस दौरान उन्होंने नजीबाबाद के विधायक पर भी कटाक्ष किया।

'मैं सनातनी हूं, ओवैसी का सिपाही हूं'

उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों के हितों की अनदेखी की है। पंडित मनमोहन ने मुसलमानों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं सनातनी हूं, ओवैसी का सिपाही हूं और ईमान में विश्वास रखता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव बड़ा बदलाव लाएगा।

राम मंदिर में चंदा चोरी पर बोले, ट्रस्ट ने गलती की

नजीबाबाद में मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन करने को तैयार है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ट्रस्ट ने गलती की है। ट्रस्ट में मुसलमान को रख देते, जब मामला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, गोली मार देते, उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता और मामला निपट जाता। लेकिन अभी चंपक को मजे हैं, पूरे चंपक मजे मे हैं। आप बताइए क्या हो रहा है। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको कस्टडी में भी नहीं लिया जाता।

पेपर लीक, बेरोजगारी और चुप विधायकों पर एनएसयूआई का हमला

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एनएसयूआई ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री के पोस्टर लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मानस तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में युवाओं की आवाज दबाई जा रही है और हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं मानो बिना घोषणा के आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए गए हों। उनका कहना था कि युवा बेरोजगारी, महंगाई और अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार उनकी मूलभूत जरूरतों और भविष्य को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। मानस तिवारी ने सुल्तानपुर के भाजपा विधायकों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के जनप्रतिनिधि छात्रों के मुद्दों, भर्ती प्रक्रियाओं और पेपर लीक जैसे मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। एनएसयूआई ने भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी पर भी सवाल उठाए। मानस तिवारी ने कहा कि छात्र हितों की बात करने वाला संगठन युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर मुखर नहीं दिख रहा और सत्ता के पक्ष में खड़ा नजर आता है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाब देगा। मानस तिवारी ने कहा कि युवाओं का भरोसा अब बदल रहा है और वे रोजगार व शिक्षा के सवाल पर राजनीतिक जवाब तय करेंगे।

पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुंचे सांसद किशोरी लाल, बोले- चंदा चोरी न रोक पाने वाले हमको दर्शन से रोक रहे

आर्यावर्त संवाददाता

अमेठी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रस्तावित अयोध्या कूच से पहले अमेठी में देर रात सियासी हलचल तेज हो गई। पुलिस ने कानून-व्यवस्था के मद्देनजर कई कांग्रेस नेताओं के घरों पर पहरा बैठा दिया। लेकिन, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा पुलिस को चकमा देकर देर रात ही अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उनके साथ जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह भी अयोध्या पहुंच गए। बुधवार सुबह गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ताला लटका मिला।

प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सुबह 9.00 बजे गौरीगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए रवाना होने का कार्यक्रम था। इससे पहले ही पुलिस ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सुमित, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ल, देवमणि तिवारी, सर्वेश सिंह, अवनीश सेनानी समेत कई नेताओं के घरों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अयोध्या पहुंचने के बाद सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि वह भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। चंदा चोरी को तो नहीं रोका जा सका, लेकिन एक हिंदू को भगवान श्रीराम के दर्शन से रोका जा रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस परंपरा में श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम के दर्शन से रोका जाता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए लोकतांत्रिक विरोध को दबा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन कार्रवाई की गई है।

इमाम हुसैन की शहादत ने करूणा का पैगाम दिया

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मस्जिद चहारसू रौजा मख्दूम शाह अढहन में शेख नूरुल हसन मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से मजलिसे हजरत इमाम हुसैन की याद में बाद नमाजे मगरिबैन आयोजित की गई । इमामत मौलाना आबिद आगा खां नजफी साहब सुल्तानपुरी ने की ,मजलिस को मौलाना सैय्यद इफ्तेखार अली जाफरी साहब पूना महाराष्ट्र ने खिताब करते हुए हजरत फात्मा को अल्लाह ने फजीलत दी है उसकी तफसीली हदीस पढी । उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की कर्बला में दी गई शहादत ने इन्सानी समाज में कुर्बानी,दया, करुणा का पैगाम दिया । इमाम हुसैन ने इन्सानियत के फलाह के लिए आपने 72 साथियों के साथ कर्बला में शहादत पेश की । इफ्तेखार जाफरी ने दस मोहर्रम को शहादत के हो जाने के बाद यजीदी फौज द्वारा उनके खानदान को गिरफ्तार करके कूफा और शाम सीरिया ले जाने पर किये गये जुल्म की दास्तान पढ़ते हुए मसायब पढ़ें मोमनीन की आंखों अश्कबार हों गई । बदरू जमा बन्ने ने सोज खानी की सैफ अब्बास ने पेश खानी की । मैनेजर शेख अली मंजर डेजी ने बताया कि यह तेरह मोहर्रम की मजलिस का 38 वा दौर है । सैय्यद परवेज हसन नेता, तालिब रजा शकीयल एडवोकेट, तहसीन अब्बास सोनी, सैय्यद अहसन रिजवी नजमी, सैय्यद असलम नकवी, मोहम्मद जाफर अब्बास नासिर रजा गुड्डू डाक्टर तकवीम रजा राहिल , अफरोज हुसैनी, नासिर अब्बास एडवोकेट इत्यादि लोग मौजूद थे।

'मां और अंकल ने तकिए से मुंह दबाकर पापा को मारा', बच्चों का खुलासा, कत्ल से पहले प्रेमी संग बनाए थे संबंध

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुए सचिन हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। अब हत्याकांड में मासूम बेटी और बेटा सामने आए हैं। उन्होंने मां और उसके प्रेमी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

नौरोजपुर गुर्जर गांव के किसान सचिन की आठ साल की बेटी और सात साल के बेटे ने पिता की हत्या की घटना के बारे में पुलिस को बताया। उन्होंने बताया कि हमारे पापा को मम्मी और एक अंकल ने तकिए से मुंह दबाकर मारा है। जब पापा की चीख निकली तो हमारी नींद खुद गई और कमरे की खिड़की से हमने सब कुछ देखा। पुलिस ने विवेचना में उनके बयान दर्ज कर लिए हैं।

नौरोजपुर गुर्जर गांव में 12 जून की रात किसान सचिन को उसकी पत्नी रचना ने खीर में नशीली गोलियां मिलाकर खिलाई थीं। सचिन के सोने पर मर्चेंट नेवी में सेकेंड क्लास इंजीनियर अपने प्रेमी सोनू निवासी रंछाड़ को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाए थे। सचिन के जागने पर दोनों ने तकिए से मुंह दबाने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी रचना और उसके प्रेमी सोनू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस अब बयान दर्ज कर रही है।

विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि इसमें सोमवार को सचिन की बेटी और बेटे के बयान दर्ज किए गए। दोनों ने बताया कि वह कमरे में सोए हुए थे। रात में उनको पापा की चीख सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई। कमरे में खिड़की लगी हुई है।

उससे बाहर झांककर देखा तो बरामदे में चारपाई पर लेटे हुए पापा के मुंह पर मम्मी व एक अंकल ने तकिया रखा हुआ था और उस तकिए से उनका मुंह दबा रहे थे। यह देखकर दोनों डरकर कमरे में अंदर जाकर लेट गए। पुलिस अब जल्द ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगी।

घटना के बारे में बताते हुए रोने लगे बच्चे

दोनों बच्चों ने पिता सचिन की हत्या के बारे में पुलिस को बताया और रोने लगे, जिन्हें परिवार वालों ने शांत कराया। पुलिस ने बच्चों व परिवार वालों को हर संभव मदद, सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नौरोजपुर गुर्जर गांव में 12 जून की रात सचिन (33) नामक व्यक्ति की उसकी पत्नी रचना और प्रेमी सोनू (निवासी रंछाड़) ने मिलकर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार, रचना ने पहले अपने पति सचिन को नशीली गोलियां मिलाकर खीर खिलाई, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। इसके बाद, उसने अपने प्रेमी सोनू को बुलाया और दोनों ने मिलकर सचिन का गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

सामान्य मौत दिखाने का प्रयास

हत्या के बाद, इस जघन्य अपराध को छिपाने और इसे एक दुर्घटना का रूप देने के लिए, रचना और सोनू ने यह कहानी गढ़ी कि सचिन की तबीयत खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय बिगड़ गई थी। शनिवार की सुबह, सचिन के भाई नवीन को रचना ने फोन कर बताया कि सचिन की तबीयत काफी खराब है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है।

परिजनों को शक और पुलिस की सक्रियता

सचिन के परिजन उसे तुरंत बड़ौत के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया। इसके बाद, एक अन्य अस्पताल में ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि, 13 जून की सुबह सचिन के गले पर मिले निशान देखकर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में रात करीब दस बजे एक युवक (पहचाना गया सोनू) सचिन के घर में प्रवेश करते हुए और सुबह तीन बजकर 28 मिनट पर बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। इस महत्वपूर्ण सुराग ने पुलिस को घटना की सच्चाई तक पहुंचने में मदद की।

पूछताछ में खुलासा और गिरफ्तारी

घटना के संबंध में जब पुलिस ने पत्नी रचना से पूछताछ की, तो वह शुरू में कीटनाशक के छिड़काव से हुई मौत की बात पर अड़ी रही। लेकिन, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज पेश की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रचना ने बताया कि प्रेमी सोनू ने ही उसे नशे की गोलियां लाकर दी थीं, जिन्हें उसने खीर में मिलाकर सचिन को खिलाया था। पति के बेहोश होने पर उसने प्रेमी को बुलाकर हत्या को अंजाम दिया।

कम लाभांश से नाराज कोटेदारों का सरकार के खिलाफ मोर्चा

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने आर्थिक तंगहाली और कम लाभांश के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से कोटेदारों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया तो अगस्त 2026 से प्रदेश के लगभग 80 हजार उचित दर विक्रेता खाद्यान्न वितरण का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में राशन वितरण के एवज में कोटेदारों को प्रति क्विंटल केवल 90 रुपये लाभांश दिया जाता है जो वर्तमान महंगाई के दौर में परिवार के भरण-पोषण और दुकान संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। संगठन ने दावा किया कि अन्य राज्यों में कोटेदारों को इससे अधिक आर्थिक सहायता मिल रही है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा और दिल्ली में 200 रुपये प्रति क्विंटल, गोवा में 230 रुपये प्रति क्विंटल तथा गुजरात में न्यूनतम 20 हजार रुपये मासिक आय की व्यवस्था बताई गई। प्रदर्शन के दौरान कोटेदारों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और कम आय के कारण राशन विक्रेताओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण सहित विभागीय कार्यों से भी खुद को अलग कर लिया जाएगा। साथ ही कहा कि हड़ताल की स्थिति में आम जनता को होने वाली किसी भी परेशानी की जिम्मेदारी शासन और राशन विभाग की होगी। इस आंदोलन को सफल बनाने और मांग पत्र सौंपने में सुल्तानपुर इकाई के पदाधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश यादव, जिला महासचिव रबीन्द्र प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष (कुड़वार) अन्सार अहमद सहित धनपतगंज, कुड़वार, दूबेपुर, जयसिंहपुर और पालिया क्षेत्र के दर्जनों राशन विक्रेता मौजूद रहे। कोटेदारों ने शासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग

जौनपुर। थाना केराकत क्षेत्र के ग्राम सरकी निवासी रामसकल पुत्र गदऊ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर अपने पुत्र भानुप्रताप की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि उनका पुत्र एक टेंट व्यवसायी के यहां कार्य करता था। 25 मई को उसे काम के बहाने बुलाया गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बाद में अस्पताल ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई।पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने कई बार पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपित पक्ष द्वारा परिवार को धमकियां दी गईं तथा समझौते का दबाव बनाया गया।मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

फिर हिंदू बना आयुष : 'मोहम्मद अली' ने पूजा की और परिवार का लिया आशीर्वाद, चर्चित धर्मांतरण मामले में नया मोड़

आर्यावर्त संवाददाता

शामली। शामली शहर के दवा कारोबारी देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। धर्मांतरण का मुद्दा उठाने वाले बघरा स्थित योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने व्हाट्सएप ग्रुप में बयान जारी कर कहा कि आयुष ने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म में वापसी कर कर ली है। उन्होंने घर में पूजा करते हुए आयुष का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है।

मोहल्ला दयानंदनगर निवासी केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष देवराज मलिक ने बेटे का धर्मांतरण कराने के आरोप में छह जून को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि काजीवाड़ा निवासी जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने संपत्ति के लिए आयुष को प्रेमजाल में फंसाया। फर्जी निकाहनामा तैयार कराकर धर्म परिवर्तन कराया था। अब वायरल वीडियो में आयुष घर के मंदिर में पूजा करने और परिजनों से आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहा है। वीडियो में भी मूल धर्म में वापसी बात कही है। पिता देवराज ने कहा कि उनके पुत्र आयुष ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है।

आंदोलन की चेतावनी पर हरकत में आया था पुलिस प्रशासन

दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक के धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों के आंदोलन करने व हिंदू महापंचायत की घोषणा करने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया था। लखनऊ व दिल्ली तक भी इस प्रकरण की गूंज गई थी। बघरा आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस प्रशासन ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो कुरैशी बस्ती में हिंदू महापंचायत करेंगे। इस चेतावनी के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।

बाद में यशवीर महाराज ने पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट होकर महापंचायत स्थगित कर दी थी। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने भी धर्मांतरण प्रकरण को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि वह आयुष मलिक का सनातन धर्म में घर वापसी करने पर हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरा हिंदू समाज उनका स्वागत करेगा। उन्होंने आयुष मलिक को सनातन धर्म में घर वापस लाने की जो लड़ाई प्रारंभ की थी, वह लड़ाई आज सफल हुई। हम मुख्यमंत्री और शामली प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।

पिता बोले- वैदिक परंपराओं को अपनाया

आयुष मलिक की सनातन धर्म में वापसी के बारे में पिता देवराज मलिक ने कहा कि ईश्वर की कृपा, माता-पिता और परिवार के स्नेह और पूर्वजों के संस्कारों के आशीर्वाद से उनके पुत्र आयुष मलिक ने पुनः सनातन वैदिक परंपराओं को अपनाते हुए पूजा-अर्चना, जप एवं धार्मिक आचरण का मार्ग स्वीकार किया है। उन्होंने इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया है।

सनातन धर्म में वापसी का मामला उनके परिवार का मामला है। वहीं इसके बारे में बता पाएंगे। धर्मांतरण के मामले में पुलिस जांच कार्रवाई कर रही है। वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एनपी सिंह, पुलिस अधीक्षक

ये था मामला

स्वामी यशवीर महाराज ने चार जून को आयुष मलिक के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर थी। छह जून को शहर कोतवाली में देवराज मलिक की तरफ से संपत्ति हड़पने के लिए जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम, भाई आसमोहम्मद, बहनें राहिल, सुमाइला व राबिया, हुमा कुरैशी, तौफीक उर्फ भोला, मौलवी मुनव्वर व दो अज्ञात मौलवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस मामले में पुलिस ने सात जून को चांदनी कुरैशी व उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद चांदनी के फुफेरे भाई सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार किया था।

महंगाई, बेरोजगारी को लेकर धरना-प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण, पेपर लीक, सरकारी स्कूलों को बंद करने तथा जनवादी अधिकारों पर बढ़ते हमले सहित अन्य जन समस्याओं के खिलाफ एस.यू.सी.आई (सी) पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर, जौनपुर में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को सम्बोधित 10 सूत्री मांग पत्रलाधिकारी को सौंपा गया। वक्ताओं ने कहा कि, जहां एक तरफ नौकरी व रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सरकार की नीतियों का विनाशकारी प्रभाव छात्रों, महिलाओं, किसानों, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों-कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटा-मोटा धंधा-व्यापार करने वालों, रिक्शा-ऑटो-टेम्पो चलाने वालों सभी पर पड़ रहा है। देशी-विदेशी बड़ी एवं एकाधिकार पूंजी को बढ़ावा देने की सरकार की नीति ने रोजगार देने वाले देश के सरकारी क्षेत्र, मध्य एवं लघु उद्योगों को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। डबल इंजन सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, व्यापार, रोजगार आदि नीतियों का असर हम सभी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान, व्यापारी, स्वरोजगार में लगे लोग सभी परेशान हैं और निराशा में आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के स्वार्थ में जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। परिणामस्वरूप जन समस्यायें लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, हत्याओं को रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है।

सबकुछ लग रहा है कंफ्यूजिंग और बार-बार भूल जाते हैं चीजें? कहीं ये ब्रेन फॉग तो नहीं

ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और एकाग्र रहने की क्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है।

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई चीज लेने गए हों, लेकिन वहां पहुंचकर ही भूल जाएं कि आखिर लेने क्या आए थे? किसी का नाम जुबान पर आकर भी याद न आए या फिर दिनभर ऐसा महसूस हो कि दिमाग किसी धुंध में घिरा हुआ है। कभी-कभार ऐसा होना तो सामान्य है, स्ट्रेस-एंग्जाइटी के कारण ये दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यदि यह समस्या बार-बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बार-बार चीजों को भूलना, ध्यान न लगना और मानसिक थकान जैसी समस्याएं कई बार ब्रेन फॉग का संकेत हो सकती हैं। ब्रेन फॉग वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग की सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और एकाग्र रहने की क्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है। कई बार वायरल संक्रमण के बाद भी लोगों में कुछ समय तक ब्रेन फॉग जैसी शिकायत देखी जाती है।

ब्रेन फॉग के बारे में जानिए

मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार लंबे समय तक बने रहने वाले मानसिक थकान, कंफ्यूजन और उलझन की समस्या के लिए ब्रेन फॉग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

अक्सर यह तनाव, ठीक से नींद न आने और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याओं के कारण होता है।

कई मामलों में विटामिन की कमी या हार्मोन्स में बदलाव जैसी अंदरूनी समस्याओं के कारण भी ब्रेन फॉग की दिक्कत हो सकती है।

ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं थायरॉयड, एनीमिया, विटामिन-बी12 की कमी, डिप्रेशन में भी देखी जाती हैं इसलिए यदि समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से कारण की जांच कराना जरूरी है।

ब्रेन फॉग की पहचान कैसे करें?

ब्रेन फॉग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ संकेत काफी सामान्य हैं।

छोटी-छोटी बातें भूल जाना, बातचीत के दौरान सही शब्द याद न आना, काम करते समय बार-बार ध्यान भटकना, निर्णय लेने में कठिनाई होना सबसे आम लक्षण है।

कुछ लोगों को हाल ही में पढ़ी हुई चीजें याद रखने में परेशानी होती है, जबकि कुछ लोगों को मीटिंग या बातचीत के दौरान बात समझने में ज्यादा समय लगता है।

यदि ये लक्षण लगातार कई सप्ताह तक बने रहें और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगें, तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।

ब्रेन फॉग की ये बातें भी जान लीजिए

हर बार कुछ भूल जाना या ध्यान भटकना ब्रेन फॉग नहीं होता। तनाव या एक साथ कई काम करने के कारण कभी-कभी किसी बात का भूल जाना सामान्य माना जाता है। लेकिन यदि भूलने की समस्या बार-बार हो, ध्यान लगाने में लगातार परेशानी आए और मानसिक स्पष्टता कम महसूस हो, तब इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

ब्रेन फॉग और डिमेंशिया जैसी गंभीर स्थितियों के लक्षण भी काफी मिलते-जुलते हैं इसलिए डॉक्टर से मिलकर सही निदान कराना जरूरी हो जाता है।

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि महिलाओं में गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण भी ब्रेन फॉग जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। थायरॉयड रोग, मधुमेह, एनीमिया, ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोगों में भी यह समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है।

क्या कम हो रही है आपकी सुनने की क्षमता? शरीर पहले ही देने लगता है ये संकेत

सुनने की क्षमता कम होना केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं है। आज के समय में तेज शोर, लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल, कुछ बीमारियां और जीवनशैली से जुड़ी कई चीजें लोगों की सुनने की क्षमता पर असर डाल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सुनने की समस्या अक्सर धीरे-धीरे शुरू होती है। शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि आसपास बहुत शोर है या सामने वाला साफ नहीं बोल रहा, लेकिन असल में यह सुनने की क्षमता में आ रही कमी का संकेत हो सकता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग सालों तक इस समस्या को पहचान नहीं पाते और जब तक इलाज के बारे में सोचते हैं, तब तक परेशानी काफी बढ़ चुकी होती है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक, कान आवाज सुनने के साथ-साथ मस्तिष्क तक सही जानकारी पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सुनने की क्षमता कम होने लगती है तो व्यक्ति बातचीत को समझने और लोगों से जुडने में मुश्किल होती है। लंबे समय तक सुनने की समस्या को नजरअंदाज करने से तनाव, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का खतरा बढ़ता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सुनने की क्षमता कम होने का पहला संकेत होता है कि कई बार लोग आवाज तो सुन लेते हैं, लेकिन शब्दों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। खासकर ऐसी जगहों पर जहां बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हों या आसपास शोर हो, वहां बातचीत समझना मुश्किल लगने लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुनने की क्षमता में शुरुआती कमी अक्सर ऊंची आवृत्ति वाली आवाजों को प्रभावित करती है। ऐसे में कुछ शब्द या अक्षर साफ सुनाई नहीं देते, जिससे बातचीत अधूरी लगती है।

एक और सामान्य संकेत बार-बार लोगों से बात दोहराने के लिए कहना है। जब यह स्थिति ज्यादा बार होने लगे, तब इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कई मामलों में परिवार के सदस्य या करीबी लोग सबसे पहले इस बदलाव को महसूस करते हैं।

सुनने की क्षमता में कमी का एक और संकेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवाज बढ़ाना भी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टीवी, मोबाइल या रेडियो की आवाज पहले की तुलना में ज्यादा तेज रखनी पड़ रही है, तो यह कानों की बदलती क्षमता का संकेत हो सकता है। चूंकि यह बदलाव धीरे-धीरे होता है, इसलिए कई लोगों को इसका एहसास नहीं होता।

फोन पर बातचीत के दौरान होने वाली परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमने-सामने बात करते समय हम सामने वाले के चेहरे के भाव, होंठों की गतिविधि और शारीरिक भाषा से भी अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन फोन पर केवल आवाज ही सहारा होती है। इसलिए सुनने की क्षमता में थोड़ी सी कमी भी फोन पर बातचीत के दौरान आसानी से महसूस हो सकती है। अगर फोन पर बातें समझने में लगातार मुश्किल हो रही है, तो यह जांच कराने का संकेत हो सकता है।

इसके अलावा कानों में लगातार घंटी, सीटी या भनभनाहट जैसी आवाज सुनाई देना भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को टिनिटस कहा जाता है। यह कई बार कानों या सुनने की प्रणाली में हो रहे बदलाव का संकेत होता है। यदि ऐसी आवाजें लंबे समय तक बनी रहें, तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।

सिर्फ हड्डियां ही नहीं, दिल पर भी पड़ सकता है विटामिन डी की कमी का असर

विटामिन डी शरीर के कई जरूरी कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में हुए रिसर्च में इसकी कमी और दिल की सेहत के बीच संबंध की भी जांच की गई है। आइए जानते हैं कि इस बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई है।

विटामिन डी शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ-साथ कई अन्य शारीरिक कार्यों में भी अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। लंबे समय तक शरीर में विटामिन डी की कमी रहने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या इसका असर सिर्फ हड्डियों तक सीमित रहता है या शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ सकता है। हाल के वर्षों में विटामिन डी और दिल की सेहत के बीच संबंध को लेकर भी कई शोध किए गए हैं। हालांकि हर व्यक्ति में इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता और इसके पीछे कई अन्य कारण भी भूमिका निभा सकते हैं।

आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लंबे समय तक घर या ऑफिस के अंदर रहना, धूप की कमी और गलत खानपान के कारण कई लोगों में विटामिन डी का स्तर कम पाया जाता है। अक्सर इसकी कमी का पता तब चलता है, जब शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं या जांच कराई जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि विटामिन डी की कमी दिल की सेहत को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसके कौन-से लक्षण दिखाई दे सकते हैं और शरीर में विटामिन डी का सही स्तर बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

विटामिन डी की कमी के कौन-से लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर बार-बार थकान महसूस होना,

सेहत कई अन्य कारकों, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान और लाइफस्टाइल से भी प्रभावित होती है। इसलिए विटामिन डी की कमी होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच और उपचार कराना जरूरी है।

मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, हड्डियों में दर्द, पीठ दर्द, बार-बार बीमार पड़ना और मूड में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों में चलने-फिरने में परेशानी या हड्डियों के कमजोर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि कई बार विटामिन डी की कमी के शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट कराकर इसकी जांच करानी चाहिए।

विटामिन डी की कमी कैसे दिल की सेहत को प्रभावित कर सकती है?

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होने और हार्ट डिजीज के बढ़े हुए जोखिम के बीच संबंध देखा गया है। विटामिन डी शरीर के कई जरूरी कार्यों में भूमिका निभाता है, जिनमें हार्ट और ब्लड वेसल्स से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। हालांकि, अब तक उपलब्ध शोध यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाए हैं कि केवल विटामिन डी की कमी ही हार्ट डिजीज का सीधा कारण बनती है या विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से हार्ट प्रॉब्लम्स का जोखिम कम हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल की

शरीर में विटामिन डी का सही स्तर बनाए रखने के लिए क्या करें?

शरीर में विटामिन डी का सही स्तर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सुबह की हल्की धूप लें और संतुलित डाइट का सेवन करें। विटामिन डी से भरपूर चीजें जैसे फैट युक्त मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध या अनाज को डाइट में शामिल किया जा सकता है। अगर जांच में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सप्लीमेंट लें। बिना सलाह के विटामिन डी की अधिक मात्रा लेना भी नुकसानदायक हो सकता है।

एटीएम गायब होने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये गलती किए तो नुकसान होना पक्का

अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एटीएम कार्ड खो जाने पर लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है। कार्ड गायब होने की बात पता चलते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, जो की स्वभाविक है। कई बार वे वे समझ नहीं पाते कि ऐसी स्थिति में पहला कदम क्या उठाना चाहिए। आपकी इसी घबराहट और अनजाने में की गई कुछ छोटी गलतियां आपके पूरे बैंक खाते को खाली कर सकती हैं।

आज के डिजिटल दौर में साइबर अपराधी आपके खोए हुए कार्ड का पल भर में गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आइए इस लेख में समझते हैं कि एटीएम कार्ड खोने के तुरंत बाद आपको कौन से जरूरी काम करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

सबसे पहले कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराएं

कार्ड गायब होते ही सबसे पहले एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाएं। इसके लिए आप अपने बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या नेट बैंकिंग या मोबाइल एप में लॉगिन करके अपने एटीएम कार्ड को सिर्फ एक मिनट के भीतर पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके कार्ड से सभी लेन-देन रोक दिए जाएंगे।

कस्टमर केयर नंबर न मिले तो एसएमएस भेजें

अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक तय फॉर्मेट में एसएमएस लिखकर बैंक के नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लिखित रूप में भी अपना कार्ड तुरंत बंद करवा सकते हैं।

पिन ढूंढने या अन्य काम में न उलझें

बहुत से लोग कार्ड खोने के बाद पैनिक होकर अपने पर्स या मोबाइल में उसका पिन नंबर ढूंढने लगते हैं। कार्ड मिलने की उम्मीद में समय बर्बाद न करें, याद रखें कि पैसे सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है, नया कार्ड तो बैंक से दोबारा आसानी से मिल जाएगा।

पुलिस में 'एनसीआर' जरूर दर्ज कराएं

कार्ड ब्लॉक करने के बाद अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एक कार्ड गायब होने की रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं। आप चाहें तो ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं। यह रिपोर्ट भविष्य में किसी भी तरह के वित्तीय फ्रॉड या अनधिकृत लेनदेन की स्थिति में आपको कानूनी रूप से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। बता दें कि अगर आपने किन्हीं कारणों की वजह से कार्ड ब्लॉक नहीं कराया तो आपके खाते से पैसे निकलने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

गर्मी का बदला मिजाज, बाजार की बदली तस्वीर: महंगे एसी की मांग घटी, शीतल पेय और आइसक्रीम की बिक्री में उछाल

इस वर्ष जून तिमाही के दौरान मौसम में लगातार बदलाव और महंगाई का असर गर्मी से जुड़े उत्पादों के बाजार पर साफ दिखाई दिया। जहां एक ओर एयर कंडीशनर (एसी) की बिक्री उम्मीद से कम रही, वहीं दूसरी ओर शीतल पेय, आइसक्रीम, दही, छाछ, डेयरी पेय और अन्य गर्मी से राहत देने वाले उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

उद्योग जगत के विशेषज्ञों के अनुसार जून महीने में कई राज्यों में बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण एयर कंडीशनर की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम महसूस हुई। दूसरी ओर महंगाई के चलते उपभोक्ताओं ने महंगे और गैर-जरूरी घरेलू उपकरणों की खरीद टालना उचित समझा। इसके विपरीत कम कीमत वाले और तुरंत उपयोग में आने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री में तेजी बनी रही।

फ्रिज और वॉशिंग मशीन की मांग बढ़ी

गोदरेज एंटरप्राइजेज समूह के उपकरण व्यवसाय के प्रमुख कमल नंदी के अनुसार इस बार शीतलन श्रेणी के उत्पादों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। उन्होंने बताया कि रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) की मांग बजट और प्रीमियम दोनों वर्गों में मजबूत बनी हुई है। वहीं मानसून के आगमन के साथ कपड़े धोने की मशीनों की मांग में भी तेजी आने लगी है।

हालांकि एयर कंडीशनर बाजार के बारे में उन्होंने कहा कि जून महीने में उत्तर भारत सहित पूरे देश में इसकी बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ वर्षों में एसी की कीमतों में लगभग 18 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता अब अपेक्षाकृत सस्ते विकल्पों, जैसे एयर कूलर और पंखों की ओर रुख कर रहे हैं।

एक अन्य प्रमुख एयर कंडीशनर कंपनी के अधिकारी ने भी माना कि इस वर्ष का ग्रीष्मकालीन कारोबार उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। हालांकि प्रीमियम मॉडल और ऊंची कीमतों के कारण उद्योग के कुल कारोबार के मूल्य में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

शीतल पेय कंपनियों को मिला लाभ

एयर कंडीशनर बाजार की सुस्ती के विपरीत शीतल पेय उद्योग ने मजबूत प्रदर्शन किया। कोका-कोला इंडिया एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया के ग्राहक विकास विभाग के उपाध्यक्ष अभिषेक गुप्ता ने बताया कि बाजार में शीतल पेय की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि तत्काल उपभोग, छोटे पैक, त्वरित वितरण सेवाओं तथा यात्रा के दौरान खरीदारी की बढ़ती प्रवृत्ति ने बिक्री को उल्लेखनीय गति दी है। कंपनी अपने सहयोगी भागीदारों के साथ मिलकर शीतलन सुविधाओं और वितरण नेटवर्क का विस्तार भी कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को हर स्थान पर आसानी से ठंडे पेय उपलब्ध हो सकें।

डेयरी और आइसक्रीम की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी

डेयरी क्षेत्र ने भी इस गर्मी शानदार प्रदर्शन किया। मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक जयतीर्थ चारी के अनुसार पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस बार जून तिमाही में कंपनी के ताजा डेयरी उत्पादों और आइसक्रीम की बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसका प्रमुख कारण आइसक्रीम, दही और डेयरी पेय की बढ़ती मांग रही।

हैवमोर आइसक्रीम के प्रबंध निदेशक देवब्रत मुखर्जी ने बताया कि कोन, स्टिक और एकल पैक वाली आइसक्रीम की बिक्री में त्वरित वितरण मंचों की वजह से उल्लेखनीय तेजी आई है।

पारंपरिक स्वादों की मांग भी बढ़ी

गर्मी के मौसम में पारंपरिक भारतीय पेय और मसालों की लोकप्रियता भी बनी रही। डीएस समूह के मसाला व्यवसाय के प्रमुख संदीप घोष के अनुसार रायता मसाला, छाछ मसाला, जलजीरा और काला नमक जैसे उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह रुझान ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी परिवारों तक देखने को मिला।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव और उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के कारण इस वर्ष गर्मी के उत्पादों का बाजार दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। जहां महंगे टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री पर दबाव रहा, वहीं कम कीमत वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों की मांग ने कंपनियों को बेहतर कारोबार का अवसर प्रदान किया।

अब ज्यादा ताकतवर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में दिया फैसला

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी जीत मिली है। कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति अब फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) जैसे स्वतंत्र सरकारी आयोगों के सदस्यों को सिर्फ नीतिगत मतभेद होने पर भी पद से हटा सकते हैं। इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां पहले से काफी बढ़ गई हैं।

यह फैसला 6-3 के बहुमत से आया। कोर्ट के छह कंजर्वेटिव जज ट्रंप के पक्ष में रहे, जबकि तीन लिबरल जजों ने इसका विरोध किया। यह मामला FTC की डेमोक्रेटिक कमिश्नर रेबेका स्लॉटर से जुड़ा था। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। ट्रंप ने 2025 में नीतियों पर मतभेद होने के कारण उन्हें पद से हटा दिया था। लेकिन उस समय कानून कहता था कि FTC कमिश्नर को केवल अक्षमता या गलत आचरण जैसे कारणों पर ही हटाया जा सकता है।

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को सीमित करता है, इसलिए यह संविधान के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि FTC देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े करीब 80 कानूनों को लागू करता है। ऐसे काम कार्यपालिका के दायरे में आते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को हटाने का अधिकार होना चाहिए।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1935 के ऐतिहासिक 'हम्फ्रीज एग्जीक्यूटर बनाम यूनाइटेड स्टेट्स' फैसले को भी पलट दिया। पिछले 91 साल से यही फैसला स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को राजनीतिक कारणों से हटाए जाने से सुरक्षा देता था। फैसले के बाद ट्रंप ने इसे बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत मिली शक्तियों की पुष्टि करता है। ट्रंप के मुताबिक, 1930 के दशक से अमेरिकी राष्ट्रपति इस अधिकार की मांग करते रहे हैं और यह राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा सबसे अहम फैसला है।

तीन जजों ने फैसले का विरोध किया

हालांकि, कोर्ट के तीनों लिबरल जजों ने इस फैसले का विरोध किया। जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने कहा कि इससे कई स्वतंत्र सरकारी आयोग अब सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाएंगे। उनके मुताबिक, इससे सरकार के भीतर शक्तियों का संतुलन बदल जाएगा और राष्ट्रपति के हाथ में जरूरत से ज्यादा ताकत आ जाएगी। रेबेका स्लॉटर ने भी फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि 91 साल पुराने फैसले को पलटना चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक, इससे कांग्रेस की भूमिका कमजोर होगी और आर्थिक फैसलों पर राष्ट्रपति का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह फैसला अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने उसी दिन फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक को हटाने की ट्रंप की कोशिश को मंजूरी नहीं दी और कहा कि फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पहले की तरह बनी रहेगी।

क्या इंजीनियरिंग टैलेंट में चीन को टक्कर दे रहा भारत? अमेरिकी अधिकारी बोले– भारत का कोई मुकाबला ही नहीं

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारत की तकनीकी ताकत को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग में आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने कहा है कि इंजीनियरिंग कार्यबल और तकनीकी प्रतिभा के मामले में भारत दुनिया का इकलौता देश है, जो चीन को चुनौती देने की क्षमता रखता है। उन्होंने भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अमेरिका का ₹अपरिहार्य साझेदार₹ बताते हुए कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई), डीप-टेक और डेवलपर इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। अमेरिका की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब दुनिया में एआई और उन्नत तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। वाशिंगटन में आयोजित नौवें यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) लीडरशिप समिट 2026 में बोलते हुए जैकब हेलबर्ग ने कहा कि भारत के पास विशाल इंजीनियरिंग कार्यबल, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उभरता हुआ तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन विकास और नई तकनीकों को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ साझा डेवलपर इकोसिस्टम विकसित करना चाहता है। जैकब हेलबर्ग ने कहा कि इंजीनियरिंग प्रतिभा की गहराई और तकनीकी कार्यबल के आकार के मामले में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जो चीन के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। उनके अनुसार भारत में तकनीकी प्रतिभाओं की बड़ी संख्या मौजूद है, जो आने वाले समय में वैश्विक तकनीकी विकास को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारत का तकनीकी इकोसिस्टम अभी तेजी से विकसित हो रहा है और वह एप्लिकेशन स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। अमेरिका का मानना है कि नई तकनीकों के व्यापक उपयोग और प्रसार में भारत की भूमिका बेहद अहम होगी। जैकब हेलबर्ग ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की थी। इस बैठक में भारत में तकनीकी निवेश, डीप-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और साझा विकास के अवसरों पर चर्चा हुई। हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निर्माण, निवेश और नवाचार के लिए तैयार हैं।

कतर में बातचीत अधर में लटकी, ट्रंप के दावे पर बोला ईरान– 'अमेरिका से मीटिंग अभी तय नहीं'

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उसके प्रतिनिधिमंडल की कतर यात्रा अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी चर्चा से जुड़ी है। ईरान की न्यूज एजेंसी के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, आने वाले दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर हमारी बातचीत की कोई बैठक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिकी प्रतिनिधियों की कतर यात्रा का ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रावधानों, जिसमें अनुच्छेद 11 भी शामिल है, के कार्यान्वयन पर आगे की कार्रवाई के लिए हो रही है। इस्माइल बघाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यापक समझौते पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है।

अंतिम समझौते के लिए बातचीत अभी नहीं

उन्होंने कहा, हम अभी अंतिम समझौते के लिए बातचीत के चरण में नहीं पहुंचे हैं। समझौता ज्ञापन (MoU) का जिक्र करते हुए बघाई ने कहा, इसके अनुच्छेद 13 के अनुसार, अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू होना अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और उनके कार्यान्वयन के जारी रहने पर निर्भर करता है। बघाई द्वारा बताए गए MoU के अनुच्छेदों में विश्वास बहाली के प्रमुख उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अंतिम समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले लागू करना आवश्यक है।

पांच प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू

आर्टिकल 11 के तहत, अमेरिका को ईरान के फ्रीज या रोके गए फंड और एसेट्स को आपसी सहमति वाली प्रक्रियाओं के तहत इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराना होगा और उन तक पहुंच आसान बनाने के लिए जरूरी लाइसेंस और मंजूरी देनी होगी। 14-पॉइंट वाले MoU के आर्टिकल 13 के अनुसार, अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू हो सकती है, जब बताए गए पांच प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू हो जाए और जारी रहे। इसका मतलब है कि व्यापक बातचीत की ओर बढ़ने से पहले दोनों पक्षों को सहमत शुरुआती उपायों पर प्रगति दिखानी होगी, जैसा कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा।

इस बीच, व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर आज (मंगलवार) ईरान के साथ बातचीत के लिए दोहा जाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद तनाव के बावजूद दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है।

वाशिंगटन के साथ समझौता करने की अपील

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक इंटरव्यू में इस घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि यह बैठक ईरान के अनुरोध पर हो रही है। लेविट ने कहा कि ट्रंप शांति प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं और उन्होंने ईरान से वाशिंगटन के साथ समझौता करने का आग्रह किया, क्योंकि पश्चिम एशिया में दुश्मनी खत्म करने के लिए 14-पॉइंट वाले समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद तकनीकी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और ईरानियों के लिए अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता करना सबसे अच्छा होगा। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब आज ही ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों पक्षों के बीच हालिया सैन्य तनाव के बाद ईरान ने अमेरिका से बैठक का अनुरोध किया था। उन्होंने घोषणा की कि तेहरान के साथ बातचीत मंगलवार (आज) को दोहा, कतर में होगी, जबकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह कोई तकनीकी बैठक निर्धारित नहीं है।

ईरान ने किया बैठक का अनुरोध: ट्रंप

'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है। यह मंगलवार को दोहा में होगी। 'एक्सियोस' (Axios) के अनुसार, कतर में होने वाली बैठक होर्मुज स्ट्रेट पर उनके विवाद को सुलझाने के लिए है। इस रणनीतिक जलमार्ग से समुद्री यातायात पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों की ओर से हाल ही में कई हमले हुए हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने 'एक्सियोस' को बताया, हमने सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है। अधिकारी ने हमलों और अन्य आक्रामक कार्रवाइयों के लिए सेना की शब्दावली का इस्तेमाल किया। एक अन्य अधिकारी ने 'एक्सियोस' को बताया कि दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटेंगे और जहाज स्वतंत्र रूप से आ-जा सकेंगे क्योंकि तकनीकी बातचीत जारी रहेगी। अमेरिकी अधिकारियों और मामले की जानकारी रखने वाले एक तीसरे सूत्र, दोनों ने मंगलवार को होने वाली बैठक की पुष्टि की। हालांकि, ईरान के सरकारी प्रसारक 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) के अनुसार, ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत इस सप्ताह तकनीकी कार्य समूह की कोई बैठक निर्धारित नहीं है।

कतर के साथ बातचीत सामान्य रूप से जारी

उन्होंने कहा कि कतर के साथ बातचीत सामान्य रूप से जारी है, खासकर दूसरे पक्ष द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के बारे में, लेकिन उन खबरों की पुष्टि नहीं हो सकी, जिनमें कहा गया है कि दोहा में तकनीकी वर्किंग ग्रुप की बातचीत चल रही है। कतर ने तेहरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत में मुख्य मध्यस्थों में से एक के तौर पर काम किया है।

तारीख और जगह पर सहमति

गरीबाबादी ने आगे कहा कि तकनीकी बातचीत का पहला दौर तभी होगा जब जरूरी शर्तें पूरी हो जाएंगी और तारीख़ और जगह पर सहमति बन जाएगी। IRIB के अनुसार, उन्होंने कहा, तकनीकी बातचीत का पहला दौर तय वर्किंग ग्रुप के दायरे में होगा, जब शर्तें पूरी हो जाएंगी और तारीख और जगह पर सहमति बन जाएगी, और इस बारे में मध्यस्थ देशों के ज़रिए बातचीत जारी है। ट्रंप की घोषणा और तेहरान के इनकार से बातचीत की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग सार्वजनिक रुख का पता चलता है, जबकि कतर उनके बीच बातचीत में मदद करना जारी रखे हुए है।

23 राजनीतिक दलों और 1 निर्दलीय सांसद ने लिखा पत्र, एसआईआर पर चीफ जस्टिस से क्या कहा?

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने कहा है कि 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र भेजा है। यह पत्र निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और चुनाव संबंधी अन्य मुद्दों पर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर यह जानकारी दी। इस पत्र में विपक्षी गठबंधन ने एसआईआर के पालन के मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में बताया कि 21 विपक्षी राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने 8 जून को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था।

अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया गठबंधन की 8 जून, 2026 की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले आदि नेता मौजूद थे। हालांकि, आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे कुछ दल बैठक से दूर रहे, लेकिन उन्होंने भी इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के दौरान घोषणा की गई कि इंडिया गठबंधन हर दो महीने में बैठकें करेगा। अगली बैठक अगस्त में तेलंगाना के हैदराबाद में होनी है।

उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है?

अमित शाह ने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठियों को व्यवस्थित प्रक्रिया से हटाया जाएगा। जहां लागू हो, उन्हें देश से निर्वासित किया जाएगा। इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने एक हालिया निर्णय में कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने का अधिकार है। न्यायालय ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग की प्रक्रिया को कानूनी वैधता प्रदान करता है।

सांसद कपिल सिब्बल ने भी हस्ताक्षर किए

इस लेटर पर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ 'ब्रायन ने बताया कि इस संयुक्त पत्र पर आम आदमी पार्टी और DMK समेत कई विपक्षी दलों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दों को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं।

एसआईआर प्रक्रिया और विवाद

चुनाव आयोग ने लगभग एक साल पहले मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को सही करना है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है। बिहार में 24 जून, 2025 को विधानसभा चुनावों से पहले इसका एक पायलट चरण शुरू हुआ था। इस अभ्यास के तहत, देश भर में मतदाता सूचियों से करीब छह करोड़ नाम हटाए गए हैं। यह पुनरीक्षण प्रक्रिया अभी भी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है।

विपक्ष के आरोप और सरकार का रुख

बिहार में अकेले 65 लाख नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य अवैध घुसपैठियों के नाम हटाना है। उनका कहना है कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक मतदाता सूची से बाहर न हो।

मानसून पर एल-नीनो का असर, जून में सामान्य से 42% कम हुई बारिश; 100 साल में तीसरा सबसे सूखा महीना

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रशांत महासागर में सक्रिय एल-नीनो का असर भारत में इस साल साफ-साफ देखने को मिल रहा है। साल 1927 से 2026 तक यह तीसरा ऐसा मौका है, जब जून का महीना सबेस सूखा साबित होने जा रहा है। महीने के अंत होने में कुछ घंटे शेष है और देश भर में 42% बारिश की कमी देखने को मिल रही है। दरअसल, जून में अब तक देश भर में औसतन केवल 92.2 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर यह आंकड़ा 157.7 मिमी होना चाहिए था। अगर आज यानी मंगलवार को जून महीने के आखिरी दिन अच्छी बारिश होती है तो कुल मिलाकर लगभग 100 मिमी बारिश होने की संभावना है। जून का महीना पिछले 100 सालों में तीन बार सूखा रहा है। मौसम इतिहास में जून महीने में इससे कम बारिश पिछले 100 सालों में सिर्फ 2009 (87.5 मिमी) और 2014 (92.1 मिमी) दर्ज की गई थी। यह दोनों साल 20 वर्षों के भीतर के ही हैं। राहत की बात यह है कि जून में जहां देश के अधिकांश हिस्सों, विशेष रूप से मध्य भारत में जहां अब तक मानसून की सबसे अधिक कमी रही है, वहां अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। IMD के अनुसार, जुलाई के पहले हफ्ते से मध्य भारत सहित देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और अच्छी बारिश होगी। बता दें कि जून के महीने में मध्य भारत में अब तक भारी वर्षा हुई है, लेकिन यह 54% तक कम है। इसके बाद पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत में 41%, उत्तर-पश्चिमी भारत में 30% और दक्षिणी भारत में 28% की कमी देखी गई है। देश के चारों तरफ इतनी भारी मात्रा में बारिश की कमी शायद इस बात का संकेत है कि एल-नीनो का प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिकी एजेंसी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सोसाइटी के अनुसार, प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती गर्मी से एल-नीनो मध्यम तीव्रता के करीब पहुंच चुका है और आने वाले महीनों में इसके और मजबूत होने की आशंका है।

'मेरे अंदर मातृत्व की भावना नहीं...' शो 'लॉकअप 2' में आकांक्षा चमोला की दो-टूक; बोलीं- गौरव मुझे छोड़ सकते हैं

हाल ही में टीवी अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला 'लॉकअप2' रियलिटी शो में अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोल रही हैं। हाल ही में उन्होंने मां न बनने के अपने फैसले के बारे में बताया। इसी वजह से उनका और गौरव का रिश्ता भी खत्म होने के कगार पर है। आकांक्षा ने 'लॉकअप 2' में ही बताया था कि वह और गौरव अलग रहे हैं और उनका तलाक होने वाला है।

लॉक अप' सीजन 2 के एक एपिसोड में आकांक्षा शो के दूसरे प्रतियोगियों श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला अपने तलाक के बारे में बात कर रही थीं। आकांक्षा ने बताया कि बहुत पहले ही अहसास हो गया था कि मां बनने की भावना उनके अंदर नहीं है। पति गौरव खन्ना को भी यह बात बता दी थी। लेकिन अब गौरव को बच्चा चाहिए, लेकिन आकांक्षा को बच्चा नहीं चाहिए। वह कहती हैं, 'गौरव बच्चे चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बच्चे नहीं दे सकती हूं। मैंने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि मेरे अंदर मातृत्व की भावना नहीं है। जब मुझे अहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं, तभी मैंने कह दिया था कि मैं मां नहीं बनूंगी। मैंने गौरव से यहां तक कह दिया कि अगर वह मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ सकते हैं।'

बता दें कि एक तरफ तो आकांक्षा चमोला कर रही हैं, वह पति गौरव खन्ना से एक साल से अलग रह रही हैं। इनका तलाक भी हो सकता है। वहीं कुछ महीनों पहले वह अपने पति और एक्टर गौरव को 'बिग बॉस 19' में सपोर्ट करती दिखी थीं। दोनों के बीच खूब प्यार नजर आया था। शो जीतने के बाद गौरव और आकांक्षा ने पार्टी की, साथ में जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर भी लगातार फोटो साझा कीं। ऐसे में फैंस को समझ नहीं आ रहा है कि इतना प्यार करने वाला कपल अलग क्यों हो रहा है? इसी वजह से फैंस को कपल की बात पर शक हो रहे हैं, वह इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि आकांक्षा चमोला का बच्चा न करना है, इस अलगाव की वजह है।

पूर्व शेफ ने काइली जेनर पर लगाए गंभीर आरोप, दर्ज हुआ मुकदमा

मॉडल काइली जेनर पर पूर्व महिला शेफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है।

मॉडल, बिजनेस वुमन काइली जेनर का मुश्किल वक्त चल रहा है। पहले उनके दो स्टाफ मेंबर्स ने काम के दौरान गलत बर्ताव को लेकर काइली पर मुकदमा दर्ज करवाया था। अब पूर्व शेफ ने भी आरोप लगाया है कि काइली के एक इवेंट के दौरान उससे मुश्किल स्थितियों में काम करवाया गया, जिससे गर्भपात हो गया। इस पूर्व शेफ ने भी अब काइली पर मुकदमा दर्ज करवाया है।

पीपल्स मैगजीन के मुताबिक लॉस एंजिल्स की एक कोर्ट में 22 जून को दायर दस्तावेजों के हिसाब से काइली जेनर पर पूर्व शेफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार काइली के सुपरवाइजर्स को अपनी हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के बारे में बताने के बावजूद उससे लंबे समय तक और शारीरिक रूप से मुश्किल काम करवाए गए।

खराब स्थिति में काम करने के कारण हुआ मिसकैरिज

शिकायत करने वाली महिला और पूर्व शेफ ने दावा किया कि उसने नवंबर 2024 में काइली जेनर के लिए काम करना शुरू किया। उस दौरान प्रेग्नेंसी से जुड़ी कुछ सुविधाओं की मांग की। हालांकि पूर्व शेफ ने आरोप लगाया कि दिसंबर में उससे भारी सामान ढलान से ऊपर लेकर जाने का कहा गया, जिससे उसे मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि 1 फरवरी 2025 को काइली जेनर के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में काम करने के दौरान शेफ को किसी तरह की मदद नहीं दी गई। इससे अगली सुबह शेफ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और बाद में पता चला कि उसका मिसकैरिज हो गया है।

क्या है पूर्व शेफ की मांग?

पूर्व शेफ मुआवजे के तौर पर बची हुई सैलरी और नौकरी से जुड़े फायदों की मांग कर रही है। वकील ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मुकदमे से ऐसी ही कंडीशन का सामना कर रहे दूसरे कर्मचारियों को भी आगे आने की हिम्मत मिलेगी।

जब तेज बुखार में भी अमिताभ बच्चन करते रहे फिल्म की शूटिंग, नीना गुप्ता ने सुनाया किस्सा

दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के काम के प्रति उनके जज्बे की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने याद किया कि कैसे अमिताभ जी ने भीषण गर्मी में तेज बुखार होने के बावजूद फिल्म 'ऊंचाई' की शूटिंग पूरी की थी।

टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक स्पेशल एपिसोड में नीना गुप्ता, अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ पहुंची थीं। वहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने ही एक दिलचस्प किस्सा सुनाया, जिसने उन पर गहरा असर डाला था।

नीना गुप्ता ने बताया, 'दिल्ली के खेतों में दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। मैं तो छांव में खड़ी थी, लेकिन अमिताभ, अनुपम और बोमन धूप में एक सीन को शूट कर रहे थे। अमिताभ ने बहुत आराम से अपना काम पूरा किया। बाद में मुझे पता चला कि उन्हें तेज बुखार था। यह देखकर मैं हैरान रह गई।'

नीना गुप्ता को मिली प्रेरणा

नीना ने आगे बताया कि इस घटना के बाद काम को लेकर उनका खुद का नजरिया बदल गया। कुछ दिनों बाद जब नीना गुप्ता की रात में शूटिंग थी, तो उन्हें बहुत तेज खांसी हो रही थी। वह बार-बार शिकायत कर रही थीं और निर्देशक से छुट्टी मांगने की सोच रही थीं। लेकिन तभी उन्हें अमिताभ बच्चन की याद आई, जो बुखार में भी धूप में डटे रहे थे।

नीना ने खुद से कहा, 'अगर अमिताभ बच्चन ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हें भी चुपचाप अपना काम करना चाहिए।' इस पर अमिताभ बच्चन ने अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'यह हमारा काम है और इसे पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, हम करेंगे।'

अनुपम खेर की भी की तारीफ

नीना गुप्ता ने सेट पर अनुपम खेर के बर्ताव की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अनुपम हमेशा सकारात्मक रहते हैं। उन्हें किसी को भी उदास देखना पसंद नहीं है और वह हमेशा दूसरों का मूड अच्छा बनाए रखते हैं।

फिल्म 'ऊंचाई' के बारे में

फिल्म 'ऊंचाई' 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता, सारिका, परिणीति चोपड़ा और डैनी डेन्जोंगपा ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म 'ऊंचाई' तीन बुजुर्ग दोस्तों की है, जो अपने एक मृत दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 'एवरेस्ट बेस कैंप' की मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं।

83 की उम्र में भी एक्टिव हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन पिछले 60 साल से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। आज 83 साल की उम्र में भी वह लगातार काम कर रहे हैं और सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्मों के अलावा, वह जल्द ही अपने मशहूर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com